बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

○ वर्ष: 23 ○ अंक: 156 ○ नई दिल्ली ○ वीरवार 19 जून 2025 ○ प्रभात कालीन ○ मूल्य: 3 रूपया ○ पृष्ठ: 8

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

हिमाचल: महिला क्रिकेट विश्वकप में दिख सकती हैं सूबे की तीन क्रिकेटर

धर्मशाला । देश में सितंबर में होने जा रहे महिला क्रिकेट विश्वकप में इस बार भारतीय टीम में तीन हिमाचली क्रिकेटरों को भी जगह मिल सकती है। हिमाचल से तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर, हरलीन देओल और तनुजा कंवर को महिला विश्व कप में खेलने का मौका मिल सकता है। रेणुका चोटिल होने के कारण पीछे तीन महीनों से एनसीए बंगलूरू में इलाज करवा रही हैं। वह जल्द ही पूरी तरह से फिट होकर भारतीय टीम में वापसी करेंगी। हरलीन देओल का इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है। वह 28 जून से इंग्लैंड में ट्राई सीरीज में खेलते नजर आएंगी। तनुजा कंवर ने हाल ही भारतीय महिला टीम में डेब्यू किया है। महिला क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम का पहला मुकाबला 30 सिंतबर को होगा।

क्लासरूम घोटाला मामले में ईडी का एक्शन, कॉन्ट्रैक्टर्स और ठेकेदारों के 37 ठिकानों पर रेड

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली में बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने क्लासरूम निर्माण घोटाला मामले में 37 ठिकानों पर छापेमारी की है। प्रवर्तन निदेशालय ने घोटाले की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कई ठिकानों पर छापा मारा है। यह घोटाला कथित तौर पर पिछली आप सरकार के दौरान हुआ था। ईडी ने दिल्ली भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की एफआईआर पर संज्ञान लेते हुए पीएमएलए के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने के बाद छापेमारी की है। ईडी ठेकेदारों और निजी संस्थाओं के कम से कम 37 ठिकानों पर तलाशी कर रही है। जानकारी के लिए बता दें कि ईडी ने 30 अप्रैल को दर्ज अपनी एफआईआर में आप के नेता और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया था। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में 12,000 से अधिक कक्षाओं या अर्ध-स्थायी संरचनाओं के निर्माण में

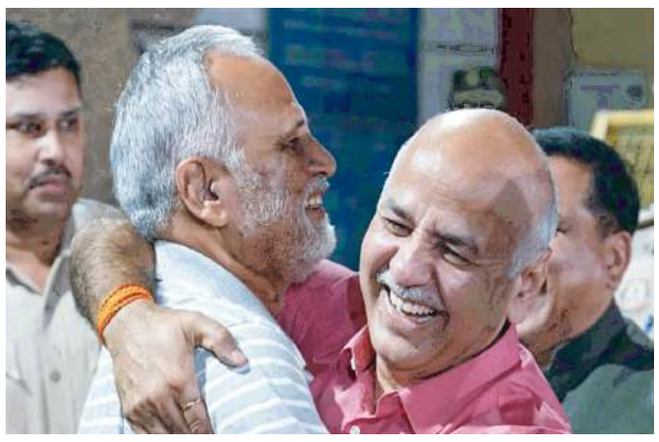

2,000 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताएं की गई थीं। दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया ने सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करने की योजना के अंतर्गत 193 स्कूलों में 2400 से अधिक कक्षाओं का निर्माण कराया था। निर्माण की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी को सौंपी गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने 17 फरवरी 2020 की एक रिपोर्ट में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओर से दिल्ली सरकार के स्कूलों में 2,400 से अधिक कक्षाओं के निर्माण में घोर अनियमितताओं को उजागर किया।

बिना निविदा के दे दिए 500 करोड़

सतर्कता आयोग ने भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद जांच में पाया कि दिल्ली सरकार ने बिना निविदा के ही प्रोजेक्ट को 500 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी मंजूर कर दी थी। यही नहीं बेहतर सुविधाओं के नाम पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 90त्न तक बढ़ाई गई। हालांकि काम घटिया दर्जे का हुआ। जीएफआर, सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल का जमकर उल्लंघन किया गया।

1214 शौचालय बनाए और उन्हें ही बता दिया कक्षा

जांच में यह भी पता चला कि 193 स्कूलों में 160 शौचालय बनाए जाने थे, लेकिन 37 करोड़ रुपये अधिक खर्च कर 1214 शौचालय बनाए गए। दिल्ली सरकार ने इन शौचालयों को कक्षा बताया और 141 स्कूलों में सिर्फ 4027 कक्षाएं ही बनाई।

आप सरकार ने ढाई साल दबाया मामला

आम आदमी पार्टी सरकार ने इस मामले को ढाई साल तक दबाया। सीवीसी ने 17 फरवरी 2020 की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार उजागर किया था और रिपोर्ट पर सतर्कता निदेशालय से जवाब मांगा। लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार ने ढाई साल तक इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। इसके बाद अगस्त 2022 में दिल्ली के एलजी ने मुख्य सचिव को निर्देश देकर देरी की जांच करके रिपोर्ट देने कहा।

राहुल गांधी के जन्मदिन पर युवाओं को तोहफा, रोजगार मेले का आयोजन करेगी युवा कांग्रेस

नई दिल्ली।

भारतीय युवा कांग्रेस कल (19 जून) राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर नई दिल्ली में एक रोजगार मेले का आयोजन करेगी। आईवाईसी अध्यक्ष उदय भानु चिब ने बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि 100 से अधिक कंपनियां मौके पर ही साक्षात्कार लेंगी और नौकरियों की पेशकश करेंगी। चिब ने एएनआई से कहा कि बीजेपी के आंकड़े बता रहे हैं कि बेरोजगारी पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा है। इसलिए फिलहाल कांग्रेस केंद्र में शासन नहीं कर रही है, ताकि हम सरकारी नौकरियों के लिए नीतियां बना सकें, लेकिन हमारा प्रयास है कि 100 से ज्यादा निजी कंपनियां आएं और युवाओं को इंटरव्यू के बाद मौके पर ही ऑफर लेटर मिल जाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन अभी पूरा नहीं हुआ है, वे भी यहां आकर मौके पर ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चिब ने बताया कि जो लोग अभी-अभी 12वीं पास हुए हैं या फिर पोस्टग्रेजुएट हैं, वे भी जॉब फेयर में हिस्सा ले सकते हैं। ÷जो लोग 10वीं से 12वीं पास कर चुके हैं, वे भी आ सकते हैं, सभी तरह की कंपनियां यहां आएंगी। चाहे वे ग्रेजुएट हों, अंडरग्रेजुएट हों या पोस्टग्रेजुएट, उनके लिए यहां नौकरी है। मैं लोगों से आग्रह करता हूं कि वे तालकटोरा स्टेडियम आएं और इसमें हिस्सा लें। जॉब फेयर 19 जून को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। आईवाईसी का दावा है कि जॉब फेयर में 100 से ज़्यादा कंपनियाँ और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हिस्सा लेंगी, जो लोगों को 5000 से ज़्यादा नौकरियाँ देंगी। इससे पहले 17 जून को चिब ने बताया था कि राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर विभिन्न राज्यों में नौकरी मेले के अलावा अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आईवाईसी रक्तदान शिविर और जाति जनगणना पर सेमिनार भी आयोजित करने जा रही है।

दिल्ली में कोरोना का कहर, एक और हुई मौत; अब तक संक्रमण से 13 की गई जान

नई दिल्ली । कोरोना से दिल्ली में एक और मौत की खबर सामने आई है। 65 वर्षीय बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया है। बुजुर्ग मुंह के कैंसर और किडनी संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे। दिल्ली में कोरोना के 620 सक्रिय मरीज और 13 लोगों मौत हो चुकी है। बीती 15 जून को कोरोना की वजह से पहली बार एक दिन में तीन लोगों की मौत हुई। कोरोना से दिल्ली में तब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी थी। जिन तीन लोगों की मौत हुई है उनमें दो महिला और एक पुरुष शामिल है। 57 वर्षीय महिला को मधुमेह, फेफड़े की समस्या थी। 57 वर्षीय पुरुष को मधुमेह, फेफड़े की समस्या थी। वहीं, 83 वर्षीय महिला को मधुमेह, उच्च रक्तचाप, फेफड़े की समस्या थी। हालांकि, कोरोना के सक्रिय मरीजों में तीन दिन से गिरावट देखी गई है। बीते शनिवार को सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 672 रह गई। कोई नया मामला भी दर्ज नहीं किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के कोविड डैशबोर्ड के अनुसार, 24 घंटे में 212 मरीजों ने कोरोना को मात दी। दिल्ली में एक जनवरी से अब तक 1960 कोरोना के मरीज सामने आए हैं जिनमें से 11 मरीजों की मौत हो गई। देश में दिल्ली कोरोना के कुल मामलों में दूसरे नंबर पर है। नए वैरिएंट्स आमतौर पर तेजी से फैलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे पहले जितने घातक हों। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे और पहले से बीमार व्यक्ति सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं। हल्के लक्षणों से शुरू होकर गंभीर सांस की दिक्कत तक मामला जा सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर घबराने या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि सर्दी जुकाम के साथ सांस लेने में दिक्कत से पीड़ित होने वाले मरीजों को डॉक्टर से मिलकर जांच कराना चाहिए।

रोज़गार नहीं, निराशा की गारंटी: मनरेगा की बदहाल स्थिति

विक्रम सिंह

पिछले दिनों मीडिया में छपी खबरों के अनुसार सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत खर्च पर कुछ पाबंदियाँ लगाई हैं। 10 जून को 'द इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित खबर के अनुसार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली छमाही के लिए मनरेगा के तहत खर्च को अपने वार्षिक आवंटन के 60 प्रतिशत पर सीमित कर दिया है। सरकार का यह निर्णय मनरेगा की मूल अवधारणा के खिलाफ है। मनरेगा मांग पर आधारित योजना है जिसमे कोई भी बेरोज़गार काम मांग सकता है। जितने मज़दूर काम मांगेंगे उतना काम देना होगा। इसमें कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए जब तक कि एक परिवार 100 दिन का रोज़गार पूरा नहीं कर लेता है। मांग के आधार पर काम मनरेगा की मूल भावना है। यह काम मज़दूर वित्तीय वर्ष में किसी भी महीने में मांग सकता है। मनरेगा कानून के अनुसार इसमें कोई भी रुकावट मज़दूरों के काम के कानूनी हक़ के खिलाफ है। इसी अवधारणा के चलते मनरेगा को वित्त मंत्रालय के सरकारी खर्च को नियंत्रण करने के नियमों से बाहर रखा गया था। गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2017 में मासिक/त्रैमासिक व्यय योजना को लागू किया था जिसका तथाकथित मक़सद मंत्रालयों को नकदी प्रवाह प्रबंधन और अनावश्यक उधारी से बचने में मदद करना था। अब तक ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आने वाले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना को इसके दायरे से बाहर रखा गया क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय का तर्क था कि यह एक मांग आधारित योजना है, जिस पर खर्च की एक निश्चित सीमा तय करना व्यवहारिक नहीं है। लेकिन वित्त वर्ष 2025ङ्क26 की शुरुआत में, वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को निर्देश दिया है कि मनरेगा को भी स्ध्क्षक्क/त्त्क्षक्क ढांचे के अंतर्गत रखा जाएगा। हालांकि भाजपानीत केंद्र सरकार के इस फैसले से किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह कोई इकलौता ऐसा फैसला नहीं है जो न केवल ग्रामीण भारत में रोज़गार मुहैया करवाने वाले मनरेगा को कमजोर करेगा बल्कि इसके तहत रोज़गार के अधिकार के भी खिलाफ है। बजट में लगातार कटौती से लेकर भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पर नित नई जटिलताएँ पैदा करने वाली तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग किये जाने वाले सभी कदम मनरेगा के मौलिक सिद्धांत को कमजोर करना ही है। मोदी सरकार अपने इन कदमों से न केवल विभिन्न अध्ययनों द्वारा मनरेगा की साबित की जा चुकी उपयोगिता को अनदेखा करती है बल्कि इससे ग्रामीण आर्थिक संकट और बेरोज़गारी की गंभीर समस्या से निपटने की सरकार की बेरुखी का भी पता चलता है। अगर उपरोक्त निर्णय लागू होता है तो इसका मतलब है कि इस वर्ष सितंबर के अंत तक इस योजना के लिए बजट के आवंटन 86,000 करोड़ का 60 प्रतिशत, केवल 51,600 करोड़ रुपए ही उपलब्ध होंगे। यह मनरेगा के अंतर्गत रोज़गार सृजन को गंभीर तौर पर प्रभावित करेगा क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा, 21,000 करोड़ रुपये पिछले वित्तीय वर्ष की लंबित देनदारियों के भुगतान में खर्च हुआ है। इस तरह के फैसले से ज़मीनी स्तर पर मांग के बावजूद मज़दूरों को मनरेगा में काम के लिए बेहिसाब तरीकों से हतोत्साहित किया जायेगा। दरअसल मनरेगा को कमजोर करने में सबसे बड़ा कारण लगातार बजट में कमी और समय पर आबंटन राज्यों तक न पहुंचना ही है। इससे ही सभी तरह की समस्याएं पैदा होती है। हालांकि हमारी वित्त मंत्री समय समय पर मीडिया में झूठे दावे करती रहती हैं कि मनरेगा के लिए फंड की कोई कमी नहीं है और काम की मांग के अनुसार इसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी लेकिन यह दावा सच्चाई से कोसों दूर है। फंड की कमी के चलते ही अघोषित तरीके से काम की मांग को नियंत्रित किया जाता है। अलग अलग तरीको से मज़दूरों को भी हतोत्साहित किया जाता है। यह बात सरकार की संसदीय समिति की 2024 की एक रिपोर्ट में भी एक बड़ी कमजोरी के तौर पर चिन्हित की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आवश्यकता के आधार पर संसाधनों की पूर्ति की जा सकती है लेकिन वर्ष के शुरुआत में अनुमानित बजट में ही फंड में कटौती करने से मनरेगा कार्यान्वयन के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलू पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए कमेटी ने जमीनी स्तर पर इस योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए फंड की कमी एक बहुत बड़ी बाधा माना है। मनरेगा के लिए शुरू में ही उपयुक्त बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए जिसका आधार पिछले वर्ष के खर्च का चलन हो सकता है। गौरतलब है कि पीपुल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी सहित देश के कई अर्थशास्त्रियों ने मनरेगा के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 2.64 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटन सुझाया है। यहां तक कि अपनी एक रिपोर्ट में विश्व बैंक ने सिफारिश की है कि इस कार्यक्रम के लिए देश की जीडीपी का कम से कम 1.7फीसदी आवंटित किया जाना चाहिए। इसके विपरीत, वर्ष 2024-25 में मनरेगा के लिए किया गया आवंटन जीडीपी का मात्र 0.26 फीसदी ही है। इस वर्ष के बजट (2025-26) में भी केवल 86000 करोड़ रुपए ही मनरेगा के लिए रखे गए हैं। यह योजना की व्यापक जरूरतों और ग्रामीण भारत की बढ़ती आर्थिक असुरक्षा के संदर्भ में बेहद अपर्याप्त है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार की प्राथमिकताओं में ग्रामीण गरीबों की आजीविका सुरक्षा को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसद की स्थायी समिति ने 22 मई को संसद में प्रस्तुत अपनी आठवीं रिपोर्ट में यह उजागर किया कि मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी भुगतान में देरी अब भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। यह देरी उन ग्रामीण मज़दूरों को प्रभावित कर रही है जो अपनी आजीविका के लिए इस योजना पर निर्भर हैं।

देश की सरकार संसद की ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसद की स्थायी समिति द्वारा लगातार दिए गए सुझावों को अनदेखा करती आ रही है लेकिन मनरेगा को कमजोर करने का कोई भी सुझाव तत्परता से लागू करती है। इसी तरह संसद की ग्रामीण विकास पर गठित एक समिति ने मनरेगा के तहत मजदूरी को कम से कम 400 रुपये प्रतिदिन करने की सिफारिश की है। इस समिति का मानना है कि वर्तमान दरें दैनिक बुनियादी खर्चों को पूरा करने के लिए भी अपर्याप्त हैं और एक न्यायसंगत मजदूरी के बिना यह योजना ग्रामीण मज़दूरों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के अपने उद्देश्य में विफल हो रही है। इसी वर्ष मार्च महीने में संसद में पेश की गई रिपोर्ट में भी समिति ने यह सिफारिश की कि ग्रामीण मजदूरी पर महंगाई के वास्तविक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मजदूरी दरों में संशोधन किया जाए। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो काफी समय से यह समिति उठाती आ रही है वह है मनरेगा के अंतर्गत मज़दूरी दरों की गणना के विसंगतिपूर्ण तरीके के बारे में। दरअसल मनरेगा के अंतर्गत मज़दूरी दरों की गणना खेत मज़दूरों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। अभी तक इसके लिए 1 अप्रैल 2009 की मूल दरों को आधार बनाकर संशोधन किया जाता है। संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस पद्धति की तीव्र आलोचना करते हुए कहा है कि 2009-2010 को आधार वर्ष मानकर की जा रही गणना अब अप्रासंगिक और निष्प्रभावी हो चुकी है, जो मौजूदा महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत के अनुरूप कोई उचित आंकड़ा देने में असमर्थ है। इससे पहले यही तर्क महेंद्र देव समिति ने भी दिया था और सुझाव दिया गया था कि मनरेगा मज़दूरी सूचकांक का आधार वर्ष 2014 होना चाहिए।

सम्पादकीय...

तीसरे विश्व युद्ध की आहट

आज की तारीख़ तक जिस प्रकार से इजराइल और ईरान भीषण युद्ध में विलीन हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ण विश्व युद्ध में लिप्त हो जाए और कोई अजब नहीं कि एटम बम तक चला दिए जाएं। वैसे भी भविष्यवाणी करने वाले नौस्त्रेदामस और बाबा वेंगा ने भी लगभग यही समय बताया था कि दुनिया समाप्त हो जाएगी और कुछ अच्छे लोगों द्वारा नई दुनिया की शुरुआत होगी। इसके अतिरिक्त कई धर्मों और विशेष रूप से इस्लाम के अनुसार क़ुरआन में भी दुनिया के खात्मे का ज़िक्र है, जिसमें यही ज़माना है कि जिसमें दुनिया को भस्म होना है, जो कि किसा भी जुम्मे (शुक्रवार) को सूर (बिगुल) फूंकने के तुरंत बाद हो सकता है जब सूरज बिल्कुल ज़मीन पर आ जाएगा। यह किसी को पता नहीं कि वह कौन सा जुम्मा होगा। वह अगला जुम्म भी हो सकता है, इस माह भी हो सकता है और 100-500 वर्ष में भी हो सकता है। दुनिया के हालात अच्छे नहीं हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि यह युद्ध मात्र इजराइल और ईरान व अमेरिका के बीच है, उनकी गलतफहमी है, क्योंकि हम अगर भविष्यवाणियों को छोड़ कर मौजूदा हालात की जांच करें तो मामलात ऐसे ही बन रहे हैं, जैसे प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के समय बन रहे थे। कुछ लोग यह भी सोच रहे हैं कि बड़े देश, जैसे अमेरिका तो सीधे इस युद्ध में जुड़ गया है, शायद चीन, रूस, नाटो, फ्रांस, उत्तरी कोरिया, भारत, ब्रिटेन, जर्मनी आदि शायद इससे अलग रहें। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बड़े देशों की अपनी सोच और फूंक अलग ही होती है। जिस प्रकार अमेरिका सोचता है कि वह सबसे अमीर और बड़े इकबाल वाला देश है, ऐसे ही कुछ और देश भी अपने बारे में यही विचार रखते हैं। यदि अमेरिका ने ईरान को समाप्त कर दिया या उसके सबसे बड़े नेता अयातुल्लाह खामिनाई को मार दिया तो चीन, रूस आदि जैसे देशों की युद्ध में जुड़ने की तटस्थ संभावना है। आज विश्व आण्विक युद्ध के ज्वालामुखी पर बैठा है और किसी भी समय दुनिया समाप्त हो सकती है। आम तौर से लोग धार्मिक ग्रंथों की इतनी नहीं मानते, मगर एक इस्लामी हदीस कहती है कि क़यामत (प्रलय) से पूर्व, कुछ लड़ाके यमन से उठेंगे और भयंकर युद्ध होगा। वैसे यमन के हूती तो आए दिन अपनी मिसाइल लाल सागर पर दागते रहते हैं। कहीं यह वही समय तो नहीं? वास्तव में यदि तीसरा विश्व युद्ध जोर पकड़ता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी इजराइल और अमेरिका पर होगी, क्योंकि एक लंबे समय से ये दोनों और कुछ अन्य पश्चिमी देश ईरान के पीछे पड़े हुए हैं कि वह अपना एटम बम बनाने का कार्यक्रम स्थगित करे, क्योंकि उससे इजराइल और अन्य देशों को ख़तरा है जबकि ईरान का दावा है कि वह अपना एटमी कार्यक्रम शांतिपूर्वक कार्यों में लगाएगा, मगर दादागीरी पर उतारू अमेरिका और इजराइल इस बात को मानने पर तैयार नहीं और पिछले दासियों साल से उस पर दबाव बना रहे हैं कि वह या तो इससे निरस्त हो या खामियाजा भुगतने को तैयार रहे। हालांकि ईरान ने कई बार यह भी कहा कि इजराइल ने जो 90 एटम बम बना रखे हैं, वह उनको समाप्त करे तो वह भी एटम बम नहीं बनाएगा, क्योंकि उसको भी उससे ख़तरा है, मगर इजराइल और अमेरिका ने ईरान की एक न सुनी और उस समय इस के एटमी कारखानों व अन्य स्थानों पर हमला करके भारी क्षति उस समय पहुंचाई जब अमेरिका और ईरान के मध्य बातचीत का छठा दौर ओमान में बीते रविवार को होने वाला था। उधर ईरान सोच रहा था कि वार्ता के लिए ओमान जेएस जाए, तभी धोखे से एक दिन पूर्व, अर्थात शनिवार को इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमला कर उसके लगभग 30 वरिष्ठ वैज्ञानिकों और सैन्य बल के अधिकारियों को पिन प्वाइंट कर टारगेट किलिंग द्वारा मार दिया और तेहरान, तबरेज आदि जैसे शहरों और सैन्य ठिकानों पर बमबारी करके सैंकड़ों निवासियों को भी मार दिया। यह वास्तव में इजराइल और अमेरिका की ओर से ईरान के साथ बड़ा धोखा किया गया है जिससे वह इतना करुद्ध है कि कहता है कि भले ही वह धरती के नक्शे से मिट जाए, इजराइल को नहीं बख्शेगा। तब से ईरान और इजराइल के मध्य ज़बरदस्त युद्ध छिड़ा हुआ है। कुछ युद्ध पंडितों का मानना है कि इस युद्ध में एटम बम का प्रयोग भी किया जा सकता है। थोड़ा सा इतिहास में जाएं तो पता चलता है कि इजराइल में यहूदी 1948 में नाज़ी ज़ुल्म से जान बचा कर फिलिस्तीन आए थे, मगर उसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि ने इजराइल को शक्तिशाली बना दिया। ईरान ने इजराइल और अमेरिका को मिटाने की बात की, जिसके चलते ईरान की अमेरिका और इजराइल से ठनी हुई है। यहां न तो ईरान को अमेरिका और इजराइल को ठिकाने लगाने की बात करनी चाहिए थी और दूसरी ओर अमेरिका को ईरान पर विश्वास करके उसके कार्यक्रम को चलते देना चाहिए था। यदि यह युद्ध नहीं रुका तो सब लोग एक इतिहास बन जाएंगे।

इजरायल ईरान सैन्य टकराव खतरनाक मोड़ पर पहुंचा

वैश्विक स्तरपर वर्तमान समय में दो दो देशों में बहुत लंबे समय से चल रहे युद्ध के पीछे चल रही ताकतों को सब जानते हैं, क्योंकि कोई भी देश क़े लिए सिर्फ अपने अकेले के बल पर इतनी ताकत से लंबी लड़ाई लड़ना संभव नहीं है, हालांकि सब जानते हैं कि इन युद्धों के पीछे कौन सी ताकत है खड़ी है? मेरा मानना है कि इन ताकतों को अपने स्टेटस को छोड़कर, दो-दो कदम आगे पीछे होकर मामला उलझा कर युद्ध विराम को प्राथमिकता देना जरूरी है,वरना किसी भी देश ने परमाणु वेपंस के इस्तेमाल की शुरुआत की तो लपेटेमें पूरी दुनियाँ आ जाएगी, जिसका परिणाम हिरोशिमा नागासाकी से भी भयंकर आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।इसलिए मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र से इस आर्टिकल के माध्यम से पर्दे के पीछे सभी देशों, गुटों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह अंध समर्थन बंद कर सुलह का रास्ता निकालकर इजरायल-ईरान- हमास, रूस-यूक्रेन सहित अनेकों देशों में आपसी टकराव को सुलझाने के लिए आगे आए ताकि पूरी दुनियाँ एक जंग का अखाड़ा ना बन सके, क्योंकि कुछ देश खुलकर समर्थन में आ रहे हैं तो कुछ देशों ने पर्दे के पीछे समर्थन देकर लड़ाई करने वाले देशों को बढ़ावा दे रहे हैं, मेरा मानना है इसे बंद कर शांति की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। हमारे पीएम साहब भी हमेशा यही अपील करते रहते हैं। परमाणु वेपंस का उपयोग हुआ तो मेरे विचार से पूरी दुनियाँ दहल जाएगी। इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, इजरायल ईरान सैन्य टकराव खतरनाक मोड़ पर पहुंच?दुनियाँ दो गुटों में बंटने की ओर बढ़ी, तीसरे विश्व युद्ध की आहट? साथियों बात अगर हम इजरायल ईरान युद्ध की करें तो दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुकाहै,इजरायल और ईरान के बीच 13-14 जून 2025 को शुरू हुआ सैन्य टकराव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, इजरायल की ओर से तेहरान में परमाणु सुविधाओं और सैन्य ठिकानों पर किए गए हवाई हमलों ने ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया,जबकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजरायल के तेल अवीव, हाइफा और बेन गुरियन एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन हमले किए। इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष हर बीतते घंटे के साथ और बढ़ता जा रहा है,सोमवार देर शाम को इजरायल ने एक बार फिर मध्य ईरान पर हवाई हमले किए, इधर ईरान ने भी इजरायल पर अब तक लगभग 400 बैलेस्टिक मिसाइलें दागने का दावा किया है, वहीं एक न्यूज से इजरायल के पीएम ने कहा है कि खामेनेई के खात्मे के साथ ही क्षेत्र में शांति आएगी। इजराइल और ईरान के बीच लगातार चौथे दिन संघर्ष जारी है। इजराइल ने सोमवार शाम सेंट्रल ईरान पर फिर से एयरस्ट्राइक की। इजराइल एयरफोर्स ने ईरानी की राजधानी तेहरान में नेशनल टीवी न्यूज चैनल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग की बिल्डिंग पर बम गिराए।घटना के समय टीवी एंकर लाइव शो होस्ट कर रही थी। वह बम धमाके में बाल-बाल बच गई। घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें एंकर को स्टूडियो से भागते हुए देखा गया। साथियों बात अगर हम इजरायल -ईरान के भयावह होते युद्ध को हम 10 प्वाइंटों में समझने की करें तो (1) इजरायल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है और दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है,इजरायल ने ईरान पर बड़ा हमला किया, जिसमें ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया. ईरान ने इजरायल के हमले का जवाब देने के लिए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस लॉन्च किया है, इसके तहत ईरान ने इजरायल पर 100 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, इजरायल की सेना ने अपने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सुरक्षित स्थानों पर शरण लें, (2) वहीं, रविवार को एक बार फिर इजरायल के आसमान में ईरानी मिसाइलों की बौछार हुई, जबकि दोनों देशों के बीच संघर्ष जारी है, इजरायल की सेना ने कहा कि ईरान की मिसाइलें आ रही हैं, यरुशलम में सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं, जबकि कई वीडियो में तेल अवीव और यरुशलम के आसमान पर मिसाइलें दिखाई दे रही हैं और उनमें से कई को इजरायल की वायु रक्षा प्रणाली द्वारा रोक दिया गया है,(3) ईरान ने शिराज शहर से इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी है, जिससे उत्तर में हाइफ़ा से लेकर दक्षिण में ईलाट तक लगभग पूरे इज़राजल में रेड अलर्ट जारी किया गया. तेल अवीव, यरुशलम, बेयर शेवा, हाइफ़ा और दर्जनों अन्य शहरों में हवाई हमले के सायरन की आवाज सुनी गईं, (4) सेना ने कहा है कि ईरानी मिसाइलों की बौछार से इजरायल में कई जगहों पर हमला हुआ है.

आरटी इंटरनेशनल की एक पोस्ट के अनुसार, ईरान के हमलों के बाद हाइफा शहर में भीषण आग देखी गई,इसने अनाम इजरायली अधिकारियों के हवाले से बताया कि अब तक इस हमले में चार लोग घायल हुए हैं, (5) ईरान में भी नज़ारा कुछ अलग नहीं है. तेहरान से आई तस्वीरों में रात के समय आसमान में ईंधन डिपो में लगी आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। यह आग इजरायल द्वारा ईरान के तेल और गैस क्षेत्र पर हमले शुरू करने के बाद लगी है, इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था और ईरानी राज्य के कामकाज पर खतरा बढ़ गया है। (6) ईरान ने शनिवार की देर रात तेल अवीव द्वारा ईरानी परमाणु संयंत्रों, मिसाइल कारखानों और सैन्य कमांड केंद्रों पर किए गए हमले के जवाब में इजरायल के हाइफा पोर्ट और पास की एक तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया, हवाई हमलों में शीर्ष सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। (7) हाइफा शहर के स्काईलाइन पर मिसाइलें नजर आईं, जिससे वहां के लोग दहशत में थे, ईरान लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमला करता रहा और इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम इन मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट करने में जुट गया,(8) पोर्ट पर रासायनिक टर्मिनल में छर्रे गिरे और कुछ अन्य मिसाइल तेल रिफाइनरी पर गिरे, लेकिन पोर्ट की सुविधाओं को कोई नुकसान नहीं हुआ, बताया जाता है कि रिफाइनरी पोर्ट से कुछ दूरी पर है, हाइफा पोर्ट उत्तरी इजरायल में स्थित एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट है, जो दक्षिण की तुलना में अपेक्षाकृत कम अस्थिर क्षेत्र है. यह देश के आयात और निर्यात दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण पोर्ट है, (9) ईरान द्वारा लगातार दूसरी रात इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद तनाव में वृद्धि हुई है. ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि हाइफा तेल रिफाइनरी पर सीधा हमला हुआ है, जिससे उत्तरी पोर्ट शहर के पास भीषण आग लग गई, मिसाइल हमला हाइफा के पास तमरा में एक आवासीय इमारत पर हुआ, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई और कम से कम 14 अन्य घायल हो गए,(10) इजरायल और ईरान ने रविवार रात को एक-दूसरे पर फिर से हमले किए, जिसमें कई लोग मारे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि संघर्ष को आसानी से समाप्त किया जा सकता है, उन्होंने तेहरान को किसी भी अमेरिकी लक्ष्य पर हमला न करने की चेतावनी भी दी, वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान में हुए हमलों में वाशिंगटन का कोई हाथ नहीं है. हालांकि, तेहरान ने इजरायली हमले में अमेरिका का हाथ होने का आरोप लगाया है और रविवार को ओमान में होने वाली परमाणु वार्ता रद्द कर दी है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि इजरायल ईरान सैन्य टकराव खतरनाक मोड़ पर पहुंचा- दुनियाँ दो गुटों में बटनें की ओर बढ़ी- तीसरे विश्व युद्ध की आहट? इजरायल-ईरान युद्ध में परमाणु हथियारों की चर्चा पर दुनियाँ सहमी। जरायल-ईरान दोनों के पीछे खड़ी ताकतों द्वारा अंधा समर्थन बंद कर,समझौते से युद्ध विराम करना जरूरी, वरना यह आग़ मिडल ईस्ट से पूरी दुनियाँ में फैलेगी।

'ड्रग्स मुक्त भारत' की दिशा में सरकार का प्रयास, समाज की जिम्मेदारी

भारत इस समय एक ऐसी चुनौती का सामना कर रहा है जो दिखने में व्यक्तिगत लग सकती है, लेकिन असल में यह एक गहरी सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी समस्या है। नशीले पदार्थों का बढ़ता सेवन केवल स्वास्थ्य संकट नहीं है। यह हमारे युवाओं की ऊर्जा, परिवारों की स्थिरता और देश की भविष्य की संभावनाओं पर एक गहरा आघात है। इस विषय को लेकर केंद्र सरकार ने समय पर गंभीरता दिखाई है और बीते कुछ वर्षों में इसे रोकने की दिशा में अनेक ठोस कदम उठाए हैं। 12 जून से 26 जून तक देश भर में 'नशामुक्त भारत पखवाड़ा' मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य न केवल जागरूकता फैलाना है, बल्कि जनता को इस प्रयास का सक्रिय भागीदार बनाना भी है। इसका समापन 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग विरोधी दिवस के अवसर पर होता है, जो विश्व स्तर पर इस संकट के प्रति एकजुटता का प्रतीक बन चुका है। भारत सरकार ने 'नशामुक्त भारत अभियान' के अंतर्गत कई स्तरों पर काम शुरू किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एन.सी.बी), राज्य पुलिस बल, स्वास्थ्य मंत्रालय और सामाजिक न्याय मंत्रालय मिलकर स्कूलों, कालेजों, ग्राम पंचायतों और नगरीय क्षेत्रों में जनजागरूकता अभियान चला रहे हैं। नुक्कड़ नाटक, ई-प्लेज, डिजिटल प्रचार और सामुदायिक संवाद के माध्यम से प्रयास हो रहे हैं कि ड्रग्स को सिर्फ अपराध नहीं, एक सामाजिक बुराई के रूप में देखा जाए। लेकिन इस समस्या का केवल सामाजिक पहलू नहीं है। यह एक सुनियोजित रणनीति का भी हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत की आंतरिक शक्ति को कमजोर करना है। सीमावर्ती क्षेत्रों से ड्रग्स की तस्करी को प्रायोजित करने वाले संगठनों और पड़ोसी देशों का उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ नहीं है, बल्कि वे भारत की युवा आबादी को कमजोर बनाकर देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर चोट करना चाहते हैं। जब कोई युवा नशे की गिरफ्त में आता है, तो वह केवल अपना ही नुकसान नहीं करता, बल्कि उसकी ऊर्जा, प्रतिभा और योगदान से देश भी वंचित रह जाता है। यह एक प्रकार का धीमा हमला है, जो बिना गोली चलाए हमारी नींव को खोखला कर सकता है। चिंता की बड़ी बात यह भी है कि ड्रग्स की काली कमाई का इस्तेमाल पड़ोसी देश की सेना भारत में आतंकी गतिविधियों को संचालित करने के लिए करती है। ऐसे में यह आवश्यक है कि हम ड्रग्स के विरुद्ध इस संघर्ष को केवल एक स्वास्थ्य या सामाजिक मुद्दा न मानें, बल्कि इसे राष्ट्र सुरक्षा से भी जोड़कर देखें। सरकार की तरफ से कानूनों को मजबूत करने और तस्करों पर कार्रवाई तेज करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। एन.डी.पी.एस.एक्ट के तहत तस्करी, भंडारण और वितरण पर सख्त दंड तय किए गए हैं, और तस्करों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी हो रही है। साथ ही, सरकार यह समझती है कि नशा करने वाले व्यक्ति को केवल अपराधी मानने से समस्या का हल नहीं होगा।

इसलिए इलाज और पुनर्वास को भी नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। 2024 में हरियाणा में विभिन्न नशामुक्ति केंद्रों और अस्पतालों में 6 लाख से अधिक लोगों ने इलाज के लिए संपर्क किया, जो यह दर्शाता है कि समाज में धीरे-धीरे जागरूकता बढ़ रही है। परंतु इलाज की सुविधाएं अब भी सीमित हैं और हर जिले में समुचित नशामुक्ति केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ परामर्श सेवाएं, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, और पुनर्वास कार्यक्रमों को भी मजबूत करने की जरूरत है। सिर्फ सरकार के प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे। यह एक ऐसी लड़ाई है, जिसमें समाज की भूमिका सबसे अहम है। माता-पिता, शिक्षक, समाजसेवी संस्थाएं, और मीडिया हर किसी को इस अभियान में सहभागी बनना होगा। युवाओं को शुरू से यह समझाना होगा कि नशा कोई 'स्टाइल' नहीं, बल्कि आत्म-विनाश का मार्ग है। हमें अपने बच्चों को सिर्फ करियर नहीं, चरित्र के बारे में भी बताना होगा। यह भी जरूरी है कि नशे को लेकर समाज में जो चुप्पी और शर्म है, उसे तोड़ा जाए। अगर किसी को नशा करने की समस्या है, तो उसे दुत्कारने की बजाय मदद की जरूरत है। जब समाज सहयोगी बनेगा, तभी कोई युवा खुलकर इलाज की ओर बढ़ेगा। हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि इस समस्या की जड़ें कहीं गहरी हैं बेरोजगारी, मानसिक तनाव, सामाजिक दबाव और संवाद की कमी। ये सभी ऐसे कारक हैं जो युवा को नशे की ओर धकेल सकते हैं। अत समाधान केवल ड्रग्स की आपूर्ति को रोकने में नहीं, बल्कि मांग को भी सामाजिक स्तर पर घटाने में है। भारत एक युवा देश है। यही युवा हमारी सबसे बड़ी शक्ति हैं और यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। अगर हम उन्हें सही दिशा दें, आत्म-विश्वास और अवसर दें, तो वे नशे जैसे किसी भी प्रलोभन को ठुकरा देंगे। इसके लिए हमें शिक्षा में सुधार, रोजगार के अवसर, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना होगा। अंतत यह हम सबकी सांझी जिम्मेदारी है। यदि सरकार प्रयास कर रही है, तो समाज को उस प्रयास को हाथ थामकर आगे ले जाना होगा। नशामुक्त भारत केवल एक संकल्प नहीं, एक राष्ट्रीय उद्देश्य है और इस दिशा में सबका सहयोग आवश्यक है।-ओ.पी. सिंह(डी.जी.पी. एवं प्रमुख, हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो)

दक्षिण के आगे चमक खोता बॉलीवुड

कहा जाता है कि दुनिया में सिर्फ सात ही कहानियां हैं, जिन्हें बदल-बदलकर सुनाया जाता है। इसी तरह बॉलीवुड में लगातार दोहराये जाने वाले सात लोग हैं- अक्षय कुमार, तीनों खान, दीपिका पादुकोण, कपूर परिवार और करण जौहर, ये लोग एक ही कहानी बार-बार दोहराते हैं। यह उक्ति हाल ही में तब सच साबित हुई, जब 'हाउसफुल-5' के ओपनिंग शो के अवसर पर पीवीआर ऑडिटोरियम एकदम खामोश दिखा। बावजूद इसके कि शीर्ष बुकिंग एप इसके 60 फीसदी टिकट बिक जाने की भ्रामक जानकारी दे रहा था, ऑडिटोरियम लगभग खाली ही था। अक्षय कुमार की यह ताजातरीन कॉमेडी फिल्म, जिसमें अभिषेक बच्चन, संजय दत्त और नाना पाटेकर समेत कुल 19 फिल्म स्टारों की मौजूदगी है, छह जून के ओपनिंग डे के दिन मात्र 24 करोड़ का ही बिजनेस कर पायी। यह फिल्म शुरुआती सप्ताह में सौ करोड़ का बिजनेस कर पाने में भी विफल रही। हताश सोशल मीडिया ने इस फिल्म को वाहियात बताया। शुरुआती 21 घंटे में यूट्यूब पर इसका ट्रेलर देखने वालों का आंकड़ा मात्र 80 लाख था, जो अक्षय कुमार की फिल्मों के लिहाज से कम था। मानो फिल्म का फ्लॉप होना ही काफी न हो, थिएटर के खालीपन से ध्यान हटाने के लिए टिकट की बिक्री को बढ़ा-चढ़ाकर बताने से संबंधित चर्चा बॉलीवुड के बड़े नामों से जुड़े संकट के बारे में बताती है। जाहिर है कि बॉलीवुड के स्टारों की चमक फीकी पड़ रही है जिससे देश के 19,000 करोड़ रुपये का मनोरंजन उद्योग खतरे में है। विडंबना यह है कि जब हिंदी सिनेमा की स्थिति डगमगा रही है तब दक्षिण भारतीय सिनेमा उभार पर है। यह बॉलीवुड में रचनात्मकता के सूखे के बारे में बताता है, 'हेराफेरी' और 'वेलकम' जैसी फिल्मों के कारण 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार की एक समय छोटे शहरों में तूती बोलती थी लेकिन 'स्काई फोर्स', 'केसरी 2' और अब 'हाउसफुल 5' जैसी उनकी फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं और 100 करोड़ का बिजनेस भी नहीं कर पायीं। 'हाउसफुल 5' को हिट कराने, खासकर बेटे अभिषेक के लिए अमिताभ की इंस्टाग्राम पर पहल भी फिल्म को दो दिन में 54 करोड़ से अधिक का बिजनेस नहीं करा पायी। 'कल्कि 2898 एडी' फिल्म में उनके रोल की चर्चा के पीछे दक्षिण भारत के दर्शकों का बड़ा योगदान है। यह बॉलीवुड के स्टारों के अब कमोबेश बाहरी तत्वों पर निर्भरता के बारे में बताता है। सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' 26 करोड़ का बिजनेस कर पायी, जबकि इसका बजट 200 करोड़ था। कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी', 18.4 करोड़ का ही बिजनेस कर पायी। हालांकि अनुपम खेर ने कंगना के निर्देशकीय नजरिये की तारीफ की लेकिन दर्शकों ने फिल्म को खारिज कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने खेर द्वारा अभिनीत 'द वैक्सीन वार' को खारिज किया था। वर्ष 2023 में 'पठान' के 1055 करोड़ के बिजनेस से शाहरुख खान ने फिर अपनी चमक बिखेरी, पर 2024 में न के बराबर फिल्म और पान मसाला विज्ञापन से जुड़े विवाद ने उनकी छवि खराब कर दी। रणबीर कपूर की एनिमल ने 553 करोड़ की कमाई की, पर 2024 में माधुरी दीक्षित के साथ 400 करोड़ रुपये की एक फिल्म वैसा बिजनेस नहीं कर पायी, जबकि 2022 की 'शमशेरा' सुपर फ्लॉप रही।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भारती ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया। सम्पादक : विजय कुमार भारती, मो0 : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2001/08863)

जाति जनगणना को जमीयत का समर्थन, मुसलमानों से अपील करते हुए बोले मदनी- ये सामाजिक और राजनीतिक जरूरत

नई दिल्ली ।आगामी जाति-आधारित जनगणना का जोरदार समर्थन करते हुए जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने इस अभ्यास को भारत में न्याय, समावेशी शासन और समान संसाधन वितरण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक बताया। मौलाना मदनी ने इस बात पर जोर दिया कि जाति-आधारित जनगणना एक नियमित सरकारी प्रक्रिया से आगे निकल गई है। उन्होंने कहा, ÷यह अब एक जरूरी सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकता है,÷ उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि एकत्र किए गए डेटा का नीति निर्माण पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, खासकर आरक्षण, सामाजिक कल्याण और विकास योजनाओं जैसे क्षेत्रों में। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सटीक डेटा लाभ और सरकारी योजनाओं तक उचित पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करेगा, खासकर हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए जिन्हें लंबे समय से नजरअंदाज किया गया है।

मुस्लिम समुदाय से सक्रिय भागीदारी का आह्वान

पूर्ण सहयोग का आग्रह करते हुए मदनी ने देश भर के सभी मुसलमानों से जनगणना प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की। उन्होंने प्रत्येक मुस्लिम परिवार से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि उनकी जाति की पहचान सही ढंग से दर्ज की गई है, उन्होंने कहा कि यह जानकारी समुदाय को प्रभावित करने वाले भविष्य के नीतिगत निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने जमीयत उलमा-ए-हिंद की स्थानीय शाखाओं, मुस्लिम संगठनों, धार्मिक संस्थानों और समुदाय के नेताओं से भी अपील की कि वे जनगणना के दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में लोगों को शिक्षित करने और प्रक्रिया के माध्यम से उनकी सहायता करने में सक्रिय भूमिका निभाएँ। संभावित चिंताओं को संबोधित करते हुए, मौलाना मदनी ने स्पष्ट किया कि जाति-आधारित जनगणना का समर्थन करना समानता के इस्लामी सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है। उन्होंने कहा, जबकि इस्लाम समानता पर आधारित समाज के विचार को कायम रखता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि भारतीय मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। उन्होंने समाज के सबसे वंचित वर्गों, विशेष रूप से पिछड़े और कम प्रतिनिधित्व वाले मुस्लिम समूहों के उत्थान के लिए नैतिक और संवैधानिक प्रतिबद्धता का आह्वान किया।

बाहरी जिला ,उपायुक्त, श्री मनोज कुमार मीना को बुद्ध का चित्र भेंट किया-विजय कुमार भारती

नई दिल्ली (आकाश शक्य) सुल्तानपुरी ,अशोक सम्राट बुद्ध विहार प्रबंधक कमिटी, republican मज़दूर संगठन तथा मीडिया सहयोगियों द्वारा बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बाहरी जिला, उपायुक्त, दिल्ली पुलिस, श्री मनोज कुमार मीना जी को तथागत गौतम बुद्ध का चित्र भेंट व पुष्प माला पहनकर स्वागत किया चित्र भेंट विजय कुमार भारती ने पुष्प माला अज़हरुद्दी ने पहनकर स्वागत किया साथ में अमित कुमार (मास्टर जी) इंद्रजीत सिंह, हिमांशु, साहिल भारती सहित कमिटी के पदाधिकारी मौजूद रहे. छाया - अशोका एक्सप्रेस, हिंदी न्यूजपेपर

मरहौरा में बना रेल इंजन दूसरे देशों की ट्रेनें घुमाएगा

नई दिल्ली । भारतीय रेलवे अपने राजस्व को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पश्चिमी अफ्रीका के तटीय देश गिनी को इंजनों का निर्यात शुरू करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को बिहार के सारण जिले के मरहौरा स्थित डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित निर्यात के लिए पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी पाटलिपुत्र (बिहार) और गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) के बीच वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह पहली बार है जब भारतीय रेलवे लोकोमोटिव का निर्यात करेगा, जिससे इसके राजस्व में वृद्धि होगी। रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पहले निर्यात लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में किया जाता था, जो विभिन्न देशों में विकास परियोजनाओं के लिए एक तरह की सहायता थी। इन इंजनों को बांग्लादेश, मोजाम्बिक जैसे देशों में भेजा गया था।

ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा- अयातुल्ला खामेनेई

- ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई ने जंग का ऐलान किया
- इजराइल पर पहली बार फतह मिसाइल से हमला
- ईरान में मौत का आंकड़ा 600 के करीब

तेहरान/तेल अवीव ।

*इजराइल में हनुमानजी की तस्वीर लेकर बंकर में छिपे भारतीय
*इजराइल बोला- ईरान में सरकारी ठिकानों पर बम गिराएंगे

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने मंगलवार देर रात इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा- जंग शुरू होती है। हम आतंकी इजराइल को कड़ा जवाब देंगे। उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। इस ऐलान के बाद ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दागीं। ईरानी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक, ईरान की सैन्य शाखा IRGC (इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स) ने कहा कि बुधवार सुबह इजराइल पर फतह मिसाइल से हमला किया गया है। यह पहली बार है जब इस जंग में फतह-1 का इस्तेमाल किया गया है। फतह मिसाइल हाइपरसोनिक है, यानी यह आवाज की गति से पांच गुना तेज उड़ती है। IRGC ने कहा कि फतह मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया और बार-बार उनके सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि इससे इजराइल को कितना नुकसान पहुंचा है, इसकी कोई सूचना नहीं है। इस बीच वॉशिंगटन स्थित एक ह्यूमनराइट्स ग्रुप ने दावा किया है कि ईरान में मौत का आंकड़ा अब 585 हो चुका है। जबकि 1,326 लोग घायल हुए हैं। ईरान की सरकार ने अब तक मौतों की पूरी जानकारी साझा नहीं की है। आखिरी बार ईरान ने सोमवार को हताहतों की जानकारी शेयर की थी। सरकार के मुताबिक इस लड़ाई 224 ईरानी मारे गए हैं, जबकि 1,277 घायल हुए हैं।

अमेरिकी दखल मंजूर नहीं

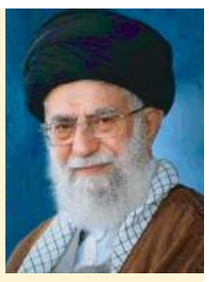

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई ने एक बयान में कहा है कि ईरान अपने शहीदों के खून को कभी नहीं भूलेगा. उन्होंने अमेरिकियों को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा और अमेरिका के किसी भी हस्तक्षेप का जोरदार जवाब देगा.

15 अगस्त से लागू होगा नया टोल सिस्टम : 3,000 में 200 ट्रिप्स फ्री

नई दिल्ली केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को टोल टैक्स को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जो देशभर के लाखों निजी वाहन चालकों को राहत पहुंचाने वाली है। उन्होंने बताया कि सरकार एक FASTag आधारित वार्षिक पास योजना शुरू करने जा रही है, जिसकी कीमत 3,000 होगी और इससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर 200 यात्राएं या एक साल (जो पहले हो) तक फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी। गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा- एक ऐतिहासिक पहल के तहत, 15 अगस्त 2025 से 3,000 की कीमत वाला FASTag आधारित वार्षिक पास शुरू किया जा रहा है। यह पास केवल गैर-व्यावसायिक निजी वाहनों (जैसे कार, जीप, वैन) के लिए वैध होगा। यह स्कीम उन लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो प्रतिदिन या बार-बार टोल प्लाजा पार करते हैं, विशेषकर वे जो 60 किलोमीटर के दायरे में यात्रा करते हैं। गडकरी ने यह भी बताया कि पास को राजमार्ग यात्रा ऐप और NHAI/MoRTH की वेबसाइट के माध्यम से सक्रिय या नवीनीकृत किया जा सकेगा। इस

प्रक्रिया को बेहद आसान और डिजिटल रूप से सुलभ बनाने की योजना है। उन्होंने यह भी कहा कि यह नई नीति टोल प्लाज़ाओं पर प्रतीक्षा समय घटाएगी, भीड़ कम करेगी और विवादों को खत्म कर यात्रियों को बेहतर अनुभव देगी। यह कदम देश की टोल प्रणाली को अधिक डिजिटल, सहज और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

पुलिस भर्ती प्रचार पर भड़कीं मायावती

बोलीं- पुलिस विभाग में भर्ती का ये रूटीन कार्य है

लखनऊ । उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने प्रदेश में हाल के दिनों में संपन्न हुई 60,244 पुलिस भर्ती पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सिलसिलेवार दो एक्स पोस्ट्स में आरोप लगाया कि सरकार जिस तरह से भर्ती को प्रचारित कर रही है जैसे कि कोई बड़ा कार्यकर दिया है। जबकि ये पुलिस विभाग में भर्ती रूटीन कार्य है, ताकि बैकलाग की बुराई पुलिस विभाग में भी न आए। किन्तु इस भर्ती में सर्व समाज को सही हक मिला या नहीं व उनकी ट्रेनिंग का क्या? यही आम चिन्ता। उन्होंने बसपा सरकार की याद दिलाते हुए कहा कि जब मेरी सरकार थी तब यूपी में 'कानून द्वारा कानून का राज' का न्याय-युक्त माहौल स्थापित करने के लिए एकमुश्त 1.20 लाख नए पद सृजित करके पुलिस भर्ती को ईमानदार बनाया गया, जिस शान्ति व्यवस्था का लाभ बिना भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लोगों को लाभ मिला, जिसकी अब काफी कमी। गौरतबल है 2007 में बसपा सरकार ने एक लाख पदों पर पुलिस विभाग में भर्ती की हुई थी।

पीएम बोले- भारत ने ना मध्यस्थता स्वीकारी थी, ना स्वीकारेंगे; सीजफायर पाक के कहने पर हुआ

नई दिल्ली।

ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी-ट्रम्प की फोन पर 35 मिनट बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज 18 जून को करीब 35 मिनट तक फोन पर गंभीर बातचीत हुई। यह वार्ता ट्रंप की पहल पर हुई, जब पीएम मोदी कनाडा में थे। उन्होंने पीएम मोदी को अमेरिका आने का न्योता भी दिया, लेकिन मोदी ने अपनी व्यस्तताओं के कारण इस दौरे को अभी असंभव बताया। यह दोनों नेताओं की सीजफायर के बाद पहली प्रत्यक्ष बातचीत थी। विदेश सचिव मिसरी ने बताया कि पीएम मोदी ने आतंकवाद पर भारत के पक्ष को रखा। दोनों नेताओं के बीच भारत पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुए तनाव पर भी चर्चा हुई। मिसरी ने बताया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी है और इस पर भी पीएम मोदी की ट्रंप से बात हुई है। दोनों नेताओं के बीच इजरायल-ईरान तनाव पर भी चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि भारत ने किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है। अमेरिका से सीजफायर पर कोई बात नहीं हुई। विदेश सचिव ने कहा कि पीएम मोदी ने यह दोहराया कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह आतंकवाद के खिलाफ भारत की सैन्य कार्रवाई है, और इसका व्यापार या कूटनीतिक समझौतों से कोई लेना-देना नहीं है। पाकिस्तान के कहने पर ही भारत ने अस्थायी सीजफायर का कदम उठाया था। मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि अब भारत आतंकवादी गतिविधियों को 'प्रॉक्सी वॉर' नहीं, बल्कि सीधा युद्ध मानकर उसका जवाब देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को बताया कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह स्पष्ट कर दिया था कि वह आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। 6-7 मई की रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया। मोदी ने कहा कि भारत अब पाकिस्तान की हर गोली का जवाब गोले से देगा।

पीएम मोदी की ट्रंप को दो टूक, साफ साफ कहा - आतंकवाद पर व्यापार नहीं, गोली का जवाब गोले से देगें

जी-7 समिट में क्यों नहीं मिल सके मोदी और ट्रंप?

दरअसल, पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कनाडा में जी-7 समिट के दौरान मुलाकात तय थी। लेकिन इजरायल-ईरान युद्ध की गंभीर स्थिति के चलते ट्रंप को 17 जून को अचानक अमेरिका लौटना पड़ा, जिससे यह बैठक नहीं हो सकी। इसके बाद ट्रंप के आग्रह पर फोन पर दोनों नेताओं की लंबी बातचीत हुई।

अगले 3 दिनों तक इन राज्यों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी

नई दिल्ली।

देश के कई इलाकों में भीषण गर्मी के बीच अब राहत की बौछारें शुरू हो चुकी हैं। जैसे-जैसे मॉनसून आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे बारिश का दायरा भी फैलता जा रहा है। दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में जहां भारी बारिश हो रही है, वहीं दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में प्री-मॉनसून की फुहारों ने मौसम को सुहाना बना दिया है। राजधानी दिल्ली में तेज हवाओं और हल्की बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, और आज के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून अब तक बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा के अधिकांश हिस्सों तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दो दिनों में यह मॉनसून गुजरात, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी अरब सागर तक और विस्तार ले सकता है। राजधानी दिल्ली में प्री-मॉनसून बारिश ने तपती गर्मी से बड़ी राहत दी है। आज शाम या रात के समय गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अगले तीन दिनों तक रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान और गिर सकता है।

नई दिल्ली(इंद्रजीत सिंह) डॉ अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, स्थित, अखिल भारतिया कांग्रेस कमिटी के अनुसूचित जाति विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री राजेंद्र पाल गौतम,पूर्व कैबिनेट मंत्री, दिल्ली सरकार को नियुक्त किये जाने पर फूल का गुलदस्ता भेंट कर शुभकामनाएं दी विजय कुमार भारती, अभय रतन गौतम और अन्य सहित . छाया-इंद्रजीत सिंह, सक्षम भारत

तमिलनाडु सरकार से न्यायालय का पूछे सवाल एडीजीपी जयराम को निलंबित करने में देरी क्यों

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को तमिलनाडु सरकार से एडीजीपी एचएम जयराम के निलंबन पर सवाल पूछे, जिन्हें अपहरण के एक मामले में उच्च न्यायालय ने हिरासत में लेने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ को राज्य सरकार के वकील ने बताया कि अधिकारी को हिरासत में लिया गया था और मंगलवार शाम 5 बजे रिहा कर दिया गया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) जयराम के वकील ने कहा कि उन्हें पुलिस ने रिहा कर दिया, लेकिन सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया है। पीठ ने कहा, ''वह एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं। उन्हें निलंबित करने की आपको क्या जरूरत थी? इस तरह के आदेश चौंकाने वाले और मनोबल गिराने वाले हैं। उन्होंने तमिलनाडु सरकार के वकील से कहा कि वह निर्देश मांगें और निलंबन रद्द करने के बारे में बृहस्पतिवार तक अदालत को अवगत कराएं। जयराम ने मद्रास उच्च न्यायालय के 16 जून के निर्देश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उच्च न्यायालय के निर्देश में पुलिस को उन्हें हिरासत में रखने के लिए कहा गया था। मंगलवार को शीर्ष अदालत ने अपहरण के एक मामले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा जयराम की गिरफ्तारी के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी। पुलिस अधिकारी के वकील ने दलील दी कि मद्रास उच्च न्यायालय का गिरफ्तारी का आदेश ''एक इकबालिया बयान पर आधारित था।

विवाद के बीच सीएम फडणवीस का आश्वासन

महाराष्ट्र के स्कूलों में अब कोई भी भारतीय भाषा तीसरा विकल्प

मुंबई । महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि राज्य में छात्रों के लिए हिंदी सीखने की अनिवार्यता को एक नए आदेश में हटा दिया गया है, और अब किसी भी भारतीय भाषा को तीसरी भाषा के रूप में चुना जा सकता है। देहू में पत्रकारों से बात करते हुए फडणवीस ने कहा कि अंग्रेजी को व्यापक रूप से बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन भारतीय भाषाओं को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है और कहा कि भाषाओं को लेकर विवाद अनावश्यक हैं। राज्य सरकार ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर कहा कि मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को हिंदी आम तौर पर तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी। संशोधित सरकारी प्रस्ताव (जीआर) में कहा गया है कि हिंदी अनिवार्य होने के बजाय आम तौर पर तीसरी भाषा होगी, और यदि किसी स्कूल में प्रति कक्षा 20 छात्र हिंदी के अलावा किसी अन्य भारतीय भाषा का अध्ययन करने की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो उन्हें इससे बाहर निकलने का विकल्प दिया गया है। कुछ मराठी समर्थक संगठनों ने सरकार पर शुरू में पीछे हटने के बाद पिछले दरवाजे से नीति को फिर से लागू करने का आरोप लगाया, और विपक्षी कांग्रेस ने सरकार पर मराठी लोगों की छाती में छुरा घोंपने का आरोप लगाया। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने पूछा कि छात्रों पर हिंदी थोपने की क्या ज़रूरत थी और राज्य के स्कूलों से अपील की कि वे सरकार के जानबूझकर भाषाई विभाजन पैदा करने के छिपे हुए एजेंडे को विफल करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदी कुछ उत्तरी राज्यों की राज्य भाषा है और इसे महाराष्ट्र पर थोपना गलत है, जहाँ मराठी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

दिल्ली के बटला हाउस में चलने जा रहा बुलडोजर! लाए गए बैरिकेड, लोग खाली कर रहे घर-दुकान

नई दिल्ली । दिल्ली के बटला हाउस में बैरिकेड आने के बाद इलाके में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जिन मकानों और दुकानों पर नोटिस चस्पा किया था, वो अब पूरी तरह से खाली हो रहें हैं. दुकानदारों ने कहा कि सामान तो पहले ही पैक कर दिया था, लेकिन अब दुकान से हटा भी रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक बटला हाउस इलाके के मुरादी रोड में डिमोलिशन को लेकर पुलिस ने बैरिकेडिंग की तैयारी की है. मुरादी रोड पर नोटिस चिपकाया गया था. कोर्ट की तरफ से मिली रोक के बाद उन प्रॉपर्टी को छोड़कर बाकी प्रॉपर्टी को डिमोलिश किया जा सकता है. दिल्ली पुलिस सुरक्षा के मद्देनजर तैयारी कर रही है. बैरिकेडिंग भी लगाया जा रहा है. बटला हाउस में डीडीए की ओर से जिन मकानों को तोड़ा जाने का नोटिस चस्पा किया गया है, उसी गली में बारात घर के पास पुलिस ने बैरिकेड लाकर रखा है. सभी बैरिकेड दीवार के किनारे साइड में रखे गए हैं. पुलिस के द्वारा बैरिकेड लाए जाने के बाद से इलाके में बुलडोजर की कार्रवाई की चर्चाएं हो रही हैं. लेकिन, इलाके में अभी तक पुलिस फोर्स की तैनाती नही की गई है. दरअसल, दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के बटला हाउस इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी. सूत्रों ने बताया कि भारी बारिश के बीच पुलिसकर्मियों को कई स्थानों पर अवरोधक लगाते देखा गया. उन्होंने बताया, ''हमने इलाके में अवरोधक लगाए हैं और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुखबिरों और सूत्रों को सक्रिय कर दिया है.''यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने बटला हाउस क्षेत्र में डीडीए द्वारा प्रस्तावित ध्वस्तीकरण पर 10 जुलाई तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति तेजस करिया ने 16 जून को जारी आदेश में डीडीए और अन्य पक्षकारों से चार सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को तय करते हुए कहा, ''इस बीच, पक्षों द्वारा यथास्थिति बनाए रखी जाएगी.

पीएम मोदी के विदेश दौरे पर आप का निशाना, भारत को क्या मिला

नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे पर निशाना साधा है. पार्टी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए पीएम मोदी पर हमला बोला गया. पोस्ट में सवाल किया गया कि पीएम मोदी की विदेश यात्राओं से भारत को मिला क्या? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी7 की बैठक छोड़कर चले गए और आज पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर से मुलाक़ात और उसके साथ लंच करेंगे. पोस्ट में आगे लिखा गया, डोनाल्ड ट्रंप भारत के दुश्मनों से मिल रहे हैं, उनके साथ लंच कर रहे हैं. लेकिन, वह भारत के किसी नेता या प्रतिनिधि दल से नहीं मिले. पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान भी मोदी के तथाकथित दोस्त भारत के साथ खड़े नहीं हुए. क्या यह मोदी सरकार की विदेश नीति की हार नहीं है? मोदी जी आपके सैकड़ों विदेश दौरे से देश को मिला क्या है?

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, किन अहम मुद्दों पर हुई चर्चा?

नई दिल्ली । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राष्ट्रीय राजधानी के विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की. रेखा गुप्ता ने कहा कि अमित शाह के साथ चर्चा सौहार्दपूर्ण, रचनात्मक और बेहद सार्थक रही. आधिकारिक बयान में कहा गया कि बैठक में दिल्ली के विकास और जन कल्याण से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया. राष्ट्रसेवा, संगठन और सुशासन के प्रति उनका दृष्टिकोण और नेतृत्व हम सभी जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणास्रोत है. दिल्ली के जनहित से जुड़े विषयों पर उनसे हुई चर्चा अत्यंत विचारोत्तेजक, मार्गदर्शक और आत्मीय रही. उनके अमूल्य समय और स्नेह के लिए हृदयपूर्वक आभार.'' मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को बताया कि दिल्ली को डबल इंजन सरकार का लाभ मिल रहा है और उनके प्रशासन ने पहले 100 दिनों में निर्धारित समय सीमा के भीतर किए गए वादों को पूरा किया है, जिसका कुछ हिस्सा केंद्र सरकार का भी है. रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार 'विकसित दिल्ली' के विजन के साथ काम कर रही है और इस मिशन में केंद्र का सहयोग महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक दोनों है. बयान में कहा गया है कि उन्होंने केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को 11 साल पूरे करने पर बधाई दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा को मजबूत किया है और आंतरिक सुरक्षा, सहकारी आंदोलनों और गरीबों के उत्थान में अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है.

भवन व अन्य सन्निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों के लिए ब्लॉक स्तर पर स्थापित होंगे हैल्प-डेस्क : अनिल विज

चण्डीगढ । हरियाणा के श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में भवन व अन्य सन्निर्माण के कार्य से जुड़े श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने हेतु पूरे प्रदेश में मण्डल स्तर (ब्लॉक स्तर) पर हैल्प-डेस्क स्थापित किए जाएंगे। श्रम मंत्री, जोकि हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन भी है, ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया कि राज्य में भवन निर्माण में लगे श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इन हैल्प-डैस्क को ब्लॉक स्तर पर स्थापित किया जाएगा, जो वन स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करेंगे। इन हैल्प डैस्कों पर श्रमिकों के पंजीकरण, विभिन्न योजनाओं के लाभ लेने हेतु सहायता, श्रमिकों को जागरूक करना और भवन निर्माण में कार्यरत श्रमिकों की समस्याओं के निवारण सम्बन्धी कार्य करने होंगे। श्री विज ने बताया कि श्रम विभाग द्वारा इन हैल्प डैस्क सेंटरों के माध्यम से भवन निर्माण से जुड़े श्रमिकों हेतु संचालित कल्याणकारी योजनाओं के आवेदनों के प्रंसस्करण में तेज़ी और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा, विभाग का वर्तमान ध्यान कनेक्ट पॉइंट्स और सेवा वितरण बिंदुओं की जमीनी स्तर की भागीदारी को भी बढाना है। इसीलिए मण्डल स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। श्री विज ने बताया कि हरियाणा में भवन निर्माण में लगे श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को लाभ प्रदान किया जाता है जिनमें मातृत्व लाभ 36 हजार रुपये, पितृत्व लाभ 21 रुपये, पंजीकृत कामगार के बच्चों की शिक्षा हेतु दिए जाने वाले लाभों के अंतर्गत बच्चों की पहली कक्षा से उच्च शिक्षा तक की वार्षिक वित्तीय सहायता 8,000 रुपये से 20,000 रुपये तक, पंजीकृत कामगारों के मेधावी बच्चों के 10वीं/12वी की परीक्षा में 60 प्रतिशत से 90 प्रतिशत अंक प्राप्ति पर 21 हजार रुपये से 51 हजार रुपए छात्रवृत्ति, वास्तविक सरकारी खर्च के अनुसार कामगार के बच्चों को प्रोफेशनल व टेक्निकल कोर्स हेतु पूर्ण शैक्षणिक व्यय की प्रतिपूर्ति, कामगार के बच्चों को व्यावसायिक संस्थानों में हॉस्टल सुविधा हेतु एक लाख 20 हजार रुपये तक सहायता राशि, पंजीकृत कामगार के बच्चों को व्यावसायिक कोर्स की कोचिंग हेतु 20 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक सहायता राशि, पंजीकृत निर्माण कर्मकार की पुत्री के लिए इलैक्ट्रिक स्कूटर की खरीद के लिए 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि और मुख्यमंत्री श्रम योगी प्रतिभावान योजना के तहत लैपटॉप हेतु 49 हजार रुपये की राशि दी जाती है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार, साइकिल की खरीद के लिए 5,000 रुपये, औजार के लिए अनुदान 8,000 रुपये, सिलाई मशीन के लिए 4,500 रुपये, मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना के तहत 5,100 रुपये, कन्यादान योजना के तहत 03 बच्चों की शादी हेतु वित्तीय सहायता (सुपुत्री) के लिए 1,01,00 रुपये, महिला श्रमिक की स्वयं की शादी हेतु वित्तीय सहायता 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। इसी तरह, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण पर वास्तविक किराए की प्रतिपूर्ति के तहत वास्तविक रेल (द्वितीय श्रेणी) बस (साधारण) किराए की भरपाई और पैतृक घर जाने पर वास्तविक किराए की प्रतिपूर्ति के तहत वास्तविक रेल (द्वितीय श्रेणी)/बस (साधारण) किराए की भरपाई की जाती है। ऐसे ही, चिकित्सा सहायता (मजदूरी क्षतिपूर्ति) के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मजदूरी की भरपाई, घातक बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता के तहत एक लाख रुपए तक सहायता, अपंगता सहायता के अंतर्गत डेढ रुपये से 3 लाख रुपए, अपंगता पेंशन 3 हजार रुपए प्रतिमाह, अक्षम बच्चों को 3 हजार रुपए वित्तीय सहायता प्रतिमाह, पेंशन (60 वर्ष उपरांत) 3,500 रुपये प्रतिमाह, पारिवारिक पेंशन 1,750 रुपये प्रतिमाह, विधवा पेंशन 3000 रुपये प्रतिमाह, मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मृत्यु पर वित्तीय सहायता के अंतर्गत कार्यस्थल पर दुर्घटना में 5,15,000 रुपये और अपंजीकृत श्रमिक की कार्यस्थल पर दुर्घटना में अपंगता होने पर डेढ लाख रुपए से 3 लाख रुपए और मृत्यु हो जाने पर वित्तीय सहायता 4 लाख रुपये दी जाती है।

पीएम मोदी-ट्रंप बातचीत पर सियासतः विपक्ष बोला- सर्वदलीय बैठक बुलाकर बताएं कि क्या बात हुई; भाजपा ने किया पलटवार

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत को लेकर भाजपा और विपक्ष आमने-सामने है। कांग्रेस-शिवसेना समेत तमाम विपक्षी दल पीएम मोदी पर निशाना साध रह हैं तो भाजपा विपक्षी दलों पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है।

सबसे पहले संजय राउत ने क्या कहा...

ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, मोदी के लोग यह कह रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप को इस बारे में ट्वीट करना चाहिए और कहना चाहिए कि वह अपने शब्द वापस लेते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जो कहेंगे, उस पर कौन विश्वास करेगा? सुधाकर बडगुजर के भाजपा में शामिल होने पर राउत ने कहा कि भाजपा एक राष्ट्रविरोधी पार्टी है। राष्ट्रवाद और देशभक्ति भाजपा के लिए सिर्फ दिखावा है। यह अब अटलजी और लालकृष्ण आडवाणीजी की पार्टी नहीं है; यह अब व्यापारियों की है। कल भाजपा ने हमारे पार्टी से एक व्यक्ति को अपनी पार्टी में ले लिया, जिस पर वे पहले देशद्रोह का आरोप लगा रहे थे। अब राष्ट्रविरोधी पार्टी कौन है? यह हमारी नहीं, बल्कि आपकी पार्टी है, जो राष्ट्रविरोधी है।

कांग्रेस ने क्या कहा?

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भोजन करने का निमंत्रण मिला है। असीम मुनीर ने जो भड़काऊ बात कही थी, उसका संबंध सीधा पहलगाम में हुए आतंकी हमले से था। मैं समझता हूं कि व्हाइट हाउस में ऐसे व्यक्ति को भोजन के लिए आमंत्रित करना हमारी कूटनीति और प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 बार यह दावा किया है कि उनकी मध्यस्थता के कारण ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया गया था। आज विदेश सचिव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 35 मिनट तक फोन पर बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी को एक सर्वदलीय बैठक रखकर इस बातचीत से विपक्ष के नेताओं को अवगत कराना चाहिए। वे (प्रधानमंत्री मोदी) संवाद से क्यों भाग रहे हैं?

राजद बोली- देश का एक स्वर अमेरिकी राष्ट्रपति तक जाना चाहिए

ऱाजद नेता मनोज झा ने प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के बीच टेली-वार्ता पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री के बयान पर कहा, मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूं कि मैं अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा करूंगा, लेकिन बात अब बहुत आगे बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने 14-15 बयान दिए हैं। आज भी एक तरफ मिस्री जी ने वीडियो जारी किया और दूसरी तरफ मैं व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग देख रहा हूं। दोनों में समन्वय, सामंजस्य की कमी है। इसलिए हम सब बार-बार कहते हैं कि संसद का सत्र तुरंत बुलाया जाना चाहिए। देश का एक स्वर अमेरिकी राष्ट्रपति तक जाना चाहिए।

भाजपा का पलटवार

भाजपा राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, विदेश सचिव ने सब कुछ बता दिया है, अब इसमें कोई भ्रम या संदेह नहीं है। भारत एक बदला हुआ भारत है जो आतंकवाद के खिलाफ किसी समझौते के मूड में नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खत्म होने तक जारी रहेगा, इस बात की इससे स्पष्ट चर्चा विश्व पटल पर नहीं हो सकती। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, आज प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो लंबी बातचीत हुई, उसमें कई बातें सामने निकलकर आई हैं। कांग्रेस पार्टी जी7 सम्मेलन और जाति जनगणना पर झूठ फैला रही थी। इसी कांग्रेस ने भारतीय सेना के विरोध में कई झूठ फैलाए थे। कांग्रेस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर भारत ने संघर्ष विराम किया था, लेकिन इनके सांसद सलमान खुर्शीद, शशि थरूर और मनीष तिवारी ने भी कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत किसी अन्य देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, देश की प्रभुसत्ता पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हम पीओके को भारत का हिस्सा मानते हैं और उसमें किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है... आज दुनिया हमारी ताकत को समझती है।

योग युक्त, नशा मुक्त हरियाणा की दिशा में मुख्यमंत्री नायब सिंह की एक ऐतिहासिक पहल

11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हरियाणा में 11 लाख से अधिक लोगों ने किया सामूहिक योगाभ्यास के लिए रजिस्ट्रेशन

चंडीगढ़ ।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग संदेश को आत्मसात करते हुए प्रदेश को योग युक्त, नशा मुक्त बनाने के संकल्प के साथ एक ऐतिहासिक पहल की है और इसी का परिणाम है कि अब तक 21 जून को योगाभ्यास करने के लिए प्रदेशभर में 11 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 21 जून को राज्य के सभी 22 जिलों और 121 खंडों में योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 11 लाख से अधिक नागरिक एक साथ भाग लेकर योग के प्रति अपनी आस्था और सहभागिता को दर्शाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम पावन ब्रह्म सरोवर, कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी व अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ योग गुरु स्वामी रामदेव की उपस्थिति में हजारों साधक योगाभ्यास करेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने के बाद 177 देशों के समर्थन से 21 जून को 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' के रूप में घोषित किया गया था। इसके माध्यम से भारत ने विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता का मार्ग दिखाया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योग फॉर वन अर्थ, वन हेल्थ है, जो शारीरिक, मानसिक और पर्यावरणीय कल्याण को बढ़ावा देने में योग की भूमिका पर प्रकाश डालती है, जो स्थिरता और एकता के लिए वैश्विक आह्वान के साथ संरेखित है। यह थीम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दिए जाने के बाद एक दशक की सफलता पर आधारित है। योग को संस्थागत रूप देने हेतु हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 व्यायामशालाएं बनाने का लक्ष्य रखा है जिनमें से अब तक 714 व्यायामशालाओं का निर्माण किया जा चुका है और 877 आयुष योग सहायकों की नियुक्ति की गई है। इन व्यायामशालाओं में भी 21 जून को विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे योग युक्त, नशा मुक्त हरियाणा का संदेश जन-जन तक पहुंचाया जाएगा।

उपभोक्ता सेवा में लापरवाही पर आरटीएस आयोग सख्त, लगाया जुर्माना

आयोग की सख्तीः बिजली उपभोक्ता को समय पर सेवा न देने पर अधिकारियों पर कार्रवाई

चंडीगढ़ ।

हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने एक उपभोक्ता की शिकायत पर गंभीरता से विचार करते हुए तीन अधिकारियों की लापरवाही के लिए जवाबदेही तय की है। आयोग के प्रवक्ता ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आयोग ने जांच में पाया कि बिजली उपभोक्ता कैथल निवासी श्री सोहन लाल द्वारा 15 मार्च 2022 को सुरक्षा राशि की वापसी के लिए दिया गया आवेदन संबंधित सहायक (सीए) को स्पष्ट रूप से मार्क किया गया था, इसके बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई । आयोग ने डिवीजन गुल्हा चीका के ड्यूटी ऑफिसर-कम-सीए श्री प्रीतम पर हरियाणा राइट टू सर्विस अधिनियम, 2014 की धारा 17(1)(द्ध) के तहत 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है तथा 5हजार रुपये उपभोक्ता को हर्जाना देने का आदेश दिया है। यह राशि जून, 2025 के वेतन से काटकर जुलाई, 2025 में भुगतान की जाएगी। 5 हजार रुपये कि राशि राज्य कोष में जमा करवाई जाएगी और 5 हजार रुपये कि राशि उपभोक्ता श्री सोहन लाल के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा, आयोग ने एफजीआरए-सह-एसडीओ (ओपी) श्री आशिष गौतम के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति की है। उन्होंने 3 जनवरी 2025 को मामले की जानकारी होने के बावजूद केवल बिल को निरस्त कर 31 जनवरी 2025 को मामला बंद कर दिया, जबकि उपभोक्ता की अपील और सुरक्षा राशि की वापसी पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। हालांकि, पहली बार चूक मानते हुए आयोग ने उन्हें चेतावनी देकर मौखिक एवं लिखित माफी स्वीकार कर ली है। डिवीजन गुल्हा चीका के अधीक्षण अभियंता श्री गौरव लोचब की भूमिका को भी आयोग ने असंतोषजनक पाया है। 3 अप्रैल 2025 को अंतिम आदेश पारित करने के बावजूद उन्होंने गलत बिल को निरस्त करने अथवा ब्याज सहित सुरक्षा राशि की वापसी की कोई ठोस पहल नहीं की। यदि आगामी 15 दिनों में उपभोक्ता को सुरक्षा राशि व देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया, तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश की जाएगी। आयोग ने अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए हैं कि वह उपभोक्ता श्री सोहन लाल को 8 हजार रुपये की सुरक्षा राशि व देय ब्याज का भुगतान कर 10 जुलाई 2025 तक आयोग को अनुपालन रिपोर्ट भेजें।

स्वास्थ्य मंत्री ने डीजीएचएस और झज्जर, गुरुग्राम और सोनीपत के सीएमओ के साथ समीक्षा बैठक की

चंडीगढ़ ।

स्वास्थ्य मंत्री ने हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं के क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की

हरियाणा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने आज अपने चंडीगढ़ आवास पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) तथा झज्जर, गुरुग्राम और सोनीपत के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं के क्रियान्वयन के विस्तृत आकलन के साथ-साथ तीनों जिलों में संसाधनों की उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने जमीनी स्तर पर मौजूदा चुनौतियों पर चर्चा की और स्वास्थ्य सेवा वितरण में सुधार के लिए चल रहे प्रयासों की समीक्षा की। कुमारी आरती सिंह राव ने सेवा वितरण में संवेदनशीलता और जवाबदेही के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ, उत्तरदायी और रोगी-केंद्रित हों, खासकर वंचित और दूरदराज की आबादी के लिए आसानी से मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता प्रत्येक नागरिक की भलाई के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक सुविधा कुशलतापूर्वक काम करे और प्रत्येक योजना अपने इच्छित लाभार्थी तक पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को बजटीय प्रावधानों, जनशक्ति आवश्यकताओं और बुनियादी ढांचे के उन्नयन के मामले में राज्य सरकार से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हरियाणा में एक मजबूत, अधिक समावेशी और लचीली सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बैठक में डीजीएचएस डॉ. मनीष बंसल, डीजीएचएस (पी) डॉ. कुलदीप सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

हरियाणा में इन लोगों को मिलेगा रोजगार, जंगल सफारी से इको टूरिज्म का नया केंद्र बनेगा हरियाणा

हरियाणा डेस्क।

हरियाणा के पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा अरावली क्षेत्र में महत्वाकांक्षी जंगल सफारी परियोजना और अरावली ग्रीन वॉल परियोजना तैयार की गई है। हरियाणा के पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा अरावली क्षेत्र में महत्वाकांक्षी जंगल सफारी परियोजना और अरावली ग्रीन वॉल परियोजना तैयार की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य न केवल इको-टूरिज्म को बढ़ावा देना है, बल्कि जैव विविधता, वन्यजीवों का संरक्षण करना और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना भी है। उन्होंने बताया कि अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली सहित चार राज्यों में फैली हुई

है और 1.15 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। केंद्र सरकार ने हरियाणा को 'अरावली ग्रीन वॉल परियोजना' और 'जंगल सफारी' की जिम्मेदारी सौंपी है, जो पर्यावरण की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगी। राव नरबीर सिंह ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के दौर में पर्यावरण संरक्षण एक वैश्विक चिंता का विषय बन गया है। उन्होंने कहा, ÷प्रकृति और वन्यजीवों के प्रति संवेदनशील होकर ही हम पर्यावरण संतुलन बनाए रख सकते हैं।÷ आज कई युवा स्टार्टअप और निजी संस्थाएं भी वन्यजीव संरक्षण में भागीदारी कर रही हैं, जिससे सरकार के प्रयासों को बल मिल रहा है। मंत्री ने बताया कि यह परियोजना पहले पर्यटन विभाग के अधीन थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार वन विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने स्वयं नागपुर में गोरेवाड़ा सफारी और गुजरात में वनतारा परियोजना का दौरा किया है। हरियाणा सरकार का लक्ष्य इस मेगा परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों कराना है। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना से देशी प्रजातियों के वनीकरण को बढ़ावा मिलेगा, मृदा स्वास्थ्य में सुधार होगा, भूजल स्तर में वृद्धि होगी और जैव विविधता का संरक्षण होगा। इससे न केवल हरियाणा का पर्यावरण मजबूत होगा, बल्कि स्थानीय युवाओं को 'वन मित्र' के रूप में अवसर मिलेंगे और हरित रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। राव नरबीर सिंह ने सभी से वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति संकल्प लेने का आह्वान किया, जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी 'मन की बात' कार्यक्रम में उल्लेख किया था।

कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की 82वीं बैठक आयोजित

चंडीगढ़ । धर्मक्षेत्र-कुरुक्षेत्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर पहचान मिले, इसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की 82वीं बैठक आज राज्यपाल एवं बोर्ड अध्यक्ष श्री बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी बतौर उपाध्यक्ष शामिल हुए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल भी उपस्थित रहे। राज्यपाल एवं बोर्ड अध्यक्ष श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि देशभर में कुरुक्षेत्र की विस्तृत पहचान बने, इसके लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करने होंगे। कुरुक्षेत्र का एक बड़ा धार्मिक महत्व है, ऐसे में एक भव्य अध्यात्मिक नगरी के रुप में इसके विस्तार को लेकर हमारी परिकल्पना होनी चाहिए। इसके बोर्ड में देश भर के विद्वान एवं प्रतिष्ठित लोगों को जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि 48 कोस के अंतर्गत आने वाले तीर्थ स्थलों को लेकर साल में कम से कम 48 उत्सव इन गांवों में मनाने चाहिए। इनमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ साथ जिन गांवों में ये तीर्थ स्थल है, उनकी सहभागिता भी जोड़ी जाए। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर पहचान मिले। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाएं कि अगर कोई यहां आएं तो उसे एहसास हो कि वो उस पवित्र धरा पर आया हैं जो महाभारत के इतिहास से जुड़ी है। इसके लिए यहां पर धार्मिक और पर्यटन के नजरिये से हमें पर्यटकों के लिए आधुनिक व्यवस्थाएं करनी होगीं। बैठक के दौरान बोर्ड के पदाधिकारियों और अधिकारियों के समक्ष कुरुक्षेत्र के विकास के पहलुओं को लेकर चर्चा हुई, जिसमें सफाई व्यवस्था, सरोवर के रख रखाव, नवीनीकरण और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करने के साथ साथ मेला एरिया में विकास को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में अलग अलग स्थानों पर चल रहे विकास कार्यो की समीक्षा की गई, साथ ही प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए।

महाभारत की थीम आएगी नजर

बैठक में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के समग्र विकास को लेकर कई पहलुओं पर चर्चा हुई है। खास तौर पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में चौक और प्रवेश द्वार को चिन्हित करने के निर्देश भी दिए है। इन्हें महाभारत की थीम का रुप दिया जाएगा। ज्योतिसर की तरफ से आने वाले रास्ते पर लगे सुदर्शन चक्र को भी दोबारा बनाया जाएगा। जिसमें लाइटिंग करने के साथ साथ भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित होगी। साथ ही बैठक में ब्रहमसरोवर के प्रवेश द्वार के नाम भी तय करने बारे चर्चा हुई। ज्योतिसर तीर्थ परिसर के आस–पास ग्रीनरी की व्यवस्था करने के भी संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए है। इसके अलावा पूरे शहर के पेंटिंग और रेलवे ब्रिज के नजदीक भी श्लोक इत्यादि लिखने बारे भी बैठक में चर्चा हुई है।

इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, पास भी बनेंगे

कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की बैठक में निर्णय हुआ है कि कुरुक्षेत्र में इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएंगी। इन बसों को 48 कोस के अंतर्गत आने वाले तीर्थो के साथ कनेक्ट किया जाएगा। बसों के अंदर रुट मैप भी लगाया जाएगा, साथ ही डेलीवेज पास की व्यवस्था भी रहेगी। बैठक में मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि डेलीवेज पास ना सिर्फ बस में चलेंगे साथ ही कुरुक्षेत्र में बने अलग अलग स्थलों पर भी एंट्री पास के रुप में भी काम आ सकेंगे। इसके साथ ही बैठक में 48 कोस के बारे में बताया गया कि बोर्ड के अधिकारियों की कमेटी द्वारा 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि में पहले चिन्हित 164 तीर्थ स्थलों के अतिरिक्त अब 18 नए तीर्थो के सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया है। इन स्थलों पर होने वाले निर्माण के डिजाइन इत्यादि को लेकर एक पीपीटी भी दिखाई गई, जिसमें विस्तार से बताया गया कि इनका डिजाइन एक तरह का होगा, साथ ही इस्तेमाल होने वाले रंग, प्रवेश द्वार, पार्क, हॉल इत्यादि भी एक प्रकार के ही बनेंगे।

4 इंफॉर्मेशन सेंटर बनाने के निर्देश

धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आने वाले तीर्थ यात्रियों अथवा पर्यटकों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए बकायदा 4 इंफॉर्मेशन सेंटर के कार्य को 15 अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए है। यह सेंटर पिपली के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन तथा ज्योतिसर में रेलवे स्टेशन और केडीबी पर बनेंगे। इन सेंटर्स के जरिए कोई भी व्यक्ति कुरुक्षेत्र के बारे में कुछ भी जान सकेंगे। बकायदा इनके पास कुरुक्षेत्र की जानकारी मुहैया करवाने वाले पोस्टर एवं बुकलैट भी उपलब्ध रहेगी।

श्री श्रवण कुमार, अधीक्षण अभियंता, पी.एम शिक्षा-2 के संरक्षण में

लो.नि.वि, शिक्षा दक्षिण-पश्चिमी अनु. डिवीजन कार्यालय बना भ्रष्टाचार का अड्डा!

कार्यपालक, सहायक, कनिष्ठ अभियंता बने ''अडानी''

ई.ई श्री विनोद कुमार पाराशर, उपखण्ड-1,2,3,4 ए.ई श्री एम.के वर्मा, विजय प्रकाश मीणा, जे.ई श्री अफ़जल आलम, श्री अमित कुमार मीणा, श्री शुभम, श्री वैभव वर्मा, श्री विकास गौतम व ठेकेदार से मिलीभगत कर विधालय भवन निर्माण में बेहद घटिया निर्माण सामग्री व अतिरिक्त वस्तु (Extra Item) व निर्माण कार्य की लागात को बढ़ाकर (Deviations) कर दिल्ली सरकार के खजाने की खुली लूट की

श्री प्रवीण सूद, निदेशक, सीबीआई, भारत सरकार से जांच की मांग

New School Building at Naseerpur, New Delhi

School Building at durga park, dwarka

School Building at Sector-16, Dwarka

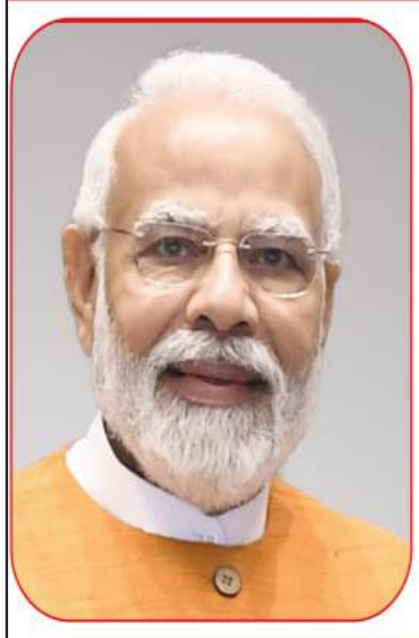

माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी, श्री अमित शाह, केन्द्रीय गृहमंत्री

से विन्रम निवेदन है कि लो.नि.वि के शिक्षा दक्षिण-पश्चिम अनुरक्षण डिवीजन के कार्यालय में तकरीबन चार वर्षो से किराए गए व कराए जा रहे है विधालयों के भवन निर्माण कार्यो की जांच सीबीआई से कराने के आदेश करो।

कार्यपालक, सहायक व कनिष्ठ अभियंता स्कूलों निर्माण कार्यो में घटिया निर्माण सामग्री, Extra Item, Deviations कर बने 'अडानी'

करोड़ो रूपये की बेनामी सम्पत्ति खरीदी अपने व अपने रिश्तेदारों के नाम, महंगी-महंगी लग्जरी कारों से चलते है, स्वयं व इनके परिवार एप्पल का मोबाईल व लेपटॉप और पी.पी.डिजाईनर के कपड़े, रोलेक्स की घड़ी, बूची के जूते, लग्जरी कारो स्वंय व परिवार के लिए प्राईवेट ड्राइवर 20-20 हजार प्रतिमाह, शाम का डिनर बड़े रेस्टुरेंट, होटल और क्लबों और लाखों की ज्वैलरी और अडानी की तरह आलीशान जिन्दगी जी रहे है।

निवेदकः अपराध एवं भ्रष्टाचार निरोधक मोर्चा

विज्ञापन-जनहित में जारी.....

Email: abnmdp@gmail.com

किसी के कहने या सुनने के बजाय खुद घटना स्थल पर जाकर लिखें खबरः रजनीकांत मणि त्रिपाठी

कसया, कुशीनगर।

***पत्रकार हित में आपसी भेद भुलाकर करें कामः सुभाष श्रीवास्तव**
***पत्रकार लोकतन्त्र का सजग प्रहरीः मनीष कुमार जायसवाल बुलबुल**
***सच लिखने की आदत डालें पत्रकार : डॉ अभिजीत**
***एबीपीएसएस द्वारा क्षेत्रीय पत्रकार मिलन समारोह का हुआ आयोजन**

अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति (एबीपीएसएस) द्वारा बुद्ध स्थली स्थित होटल देव इन में क्षेत्रीय पत्रकार मिलन समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें वक्ताओं ने देश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग सरकार से की। बुधवार को आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी पत्रकार का व्यक्तित्व असाधारण होता है। वह अपने व्यक्तित्व से दुनिया को बदल सकता है। हियर सेंस के बजाय खुद घटना स्थल पर जाकर खबर लिखें। जो देखें वह लिखें। पत्रकार सुरक्षा कानून के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम सब की जिम्मेदारी है कि इस मुहिम को नैतिक समर्थन दें। वरिष्ठ पत्रकार सोनू शुक्ला ने कहा कि पत्रकारों को सच लिखने की आदत डालनी चाहिए। जो देखें लिखें। पक्षकार बनने की जरूरत नहीं। उसी से पत्रकार जाना जाएगा। कहीं सुरक्षा का सवाल नहीं है। खुद में चेतना जागृत करें। वरिष्ठ पत्रकार सुभाष लाल श्रीवास्तव ने कहा कि आपसी भेद भुलाकर पत्रकार हित में आगे आकर संघर्ष करें। डॉ ओम प्रकाश द्विवेदी ओम ने कहा कि पत्रकार अपने अस्तित्व को लेकर चिंतित हों और पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। नपा पडरौना अध्यक्ष प्रतिनिधि मनीष कुमार जायसवाल बुलबुल ने कहा कि पत्रकार लोकतन्त्र का सजग प्रहरी है। डॉ नन्द रतन महाथेरा, समाजसेवी ओम प्रकाश जायसवाल, प्रदेश सचिव विपिन कांत सिंह, प्रदेश संयोजक आरके भट्ट, जिलाध्यक्ष बिजनौर हासिम अहमद, महिला विंग संयोजिका मनीषा सिंह चौहान, बिहार प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, राजकुमार, एसएन शुक्ल, मिथिलेश्वर पाण्डेय आदि ने संबोधित किया। अतिथियों का स्वागत क्षेत्रीय महा सचिव विजय राव, मंडल अध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा, अजय सिंह, जिला उपाध्यक्ष सतीश पांडेय, विनय तिवारी, विजय यादव, जिला महा मंत्री विनोद तिवारी, ज्ञानेश्वर बरनवाल, तहसील अध्यक्ष गण कामख्या नारायण मिश्रा, अर्जुन वेदांत, आशुतोष दीक्षित, जिला कोषाध्यक्ष पवन कुमार शर्मा, मनीष गुप्ता, अबुल आकिब अंसारी (मुन्ना), मस्तराज शर्मा आदि ने माल्यार्पण किया और मोमेंटो, अंगवस्त्र व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आभार प्रदेश अध्यक्ष अजय प्रताप नारायण सिंह ने व्यक्त किया। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष हृदया नन्द शर्मा, संचालन कवि संतोष संगम ने किया। इस दौरान संजय चाणक्य, डीके पाण्डेय, एससी चंदन, सुधाकर उपाध्याय, बृज बिहारी त्रिपाठी, मुन्ना राय, योगेश गोविंद राव, शीतल सिंह, एडवोकेट सुमन सिंह, संदीप सिंह, सरफराज आलम, असलम अंसारी, सौरभ मणि, मंतोष जायसवाल, फैजुल हक, वीरेंद्र यादव, रामाश्रय कन्नौजिया, रोटरी क्लब कोषाध्यक्ष दुर्गेश चतुर्वेदी, गौरव मिश्रा, संदीप जायसवाल, नितेश सिंह सहित भारी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे।

एक नजर

पिता से ही मिली समाजसेवा की सीख : वीरेंद्र चौधरी

फरेंदा, महराजगंज। फरेंदा विधायक वीरेंद्र चौधरी के पिता स्व0 इंद्रासन चौधरी की पुण्यतिथि बुधवार को उनके गांव सिंहपुर अयोध्या मे मनाई गई ।

पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में विधायक की अभिव्यक्ति

जहां पिता के समाधि स्थल पर विधायक वीरेंद्र चौधरी ने नम आंखो से श्रद्धांजलि दी। भावुक पलो के बीच उन्होंने पिता से ही समाजसेवा की सीख मिलने की बात कही । श्रद्धांजलि सभा का आयोजन सुबह नौ बजे से प्रारंभ हुआ । जहां परिजनों के साथ ही जिले भर के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता व अन्य दलों के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम मे विधायक वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि पिता को हमेशा दूसरों की भलाई करते देख समाज के लोगों के लिए कुछ करने की प्रेरणा जागृत हुई । उन्होंने कहा कि पिता की विचारधारा को जनसेवा के माध्यम से आगे बढ़ाते रहेंगे। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष विजय सिंह एडवोकेट, सपा जिलाध्यक्ष विद्यासागर यादव , पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रदीप चौधरी, पूर्व प्रमुख विनोद चौधरी,डॉ.अजय चौधरी,जयप्रकाश लाल, वरिष्ठ पत्रकर सुधेश मोहन श्रीवास्तव, राहुल शर्मा ,चंदन तिवारी , राजेश मौर्य, रवि प्रकाश श्रीवास्तव , राजदेव यादव , हनुमान प्रसाद व संदेश जायसवाल आदि लोग मौजूद रहे।

किसानों की समस्याओं के समाधान की दिशा में सार्थक पहल, सीडीओ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ किसान दिवस

देवरिया।

जिले के गांधी सभागार, विकास भवन में बुधवार को आयोजित मासिक किसान दिवस कार्यक्रम ने एक बार फिर कृषकों की जमीनी समस्याओं को प्रशासनिक मंच पर मजबूती से रखने का कार्य किया। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्यूष पाण्डेय की अध्यक्षता में सम्पन्न इस कार्यक्रम में किसानों की शंकाओं, शिकायतों और सुझावों पर गंभीर मंथन हुआ तथा समाधान के स्पष्ट आश्वासन दिए गए। कार्यक्रम की शुरुआत उप कृषि निदेशक सुभाष मौर्य द्वारा पिछले किसान दिवस में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की जानकारी से हुई। उन्होंने किसानों को कीटनाशी रसायनों के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए रसायनों के संतुलित उपयोग पर जोर दिया और कृषि विभाग की योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। भारतीय किसान यूनियन के मंडल प्रवक्ता इंजीनियर अतुल मिश्रा ने सुझाव रखा कि धान की फसल के लिए जरूरी खरपतवारनाशी दवाएं तथा सल्फर व पोटाश की दो-दो किलोग्राम की छोटी पैकिंग में दवाएं कृषि रक्षा इकाइयों पर उपलब्ध कराई जाएं ताकि छोटे किसानों को भी इसका लाभ मिल सके। उन्होंने भलुअनी स्थित कृषि बीज भंडार मार्ग से अवैध अतिक्रमण हटवाने की मांग की, जिस पर उप कृषि निदेशक ने शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिया। बैठक में एक महत्वपूर्ण सुझाव यह भी रहा कि प्रत्येक मासिक किसान दिवस में राजस्व विभाग के अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य की जाए ताकि भूमि संबंधी विवादों का समयबद्ध समाधान हो सके। धान की फसल में प्रयुक्त होने वाले कीटनाशकों की जानकारी देते हुए विषय वस्तु विशेषज्ञ धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रेटिलाक्योर 50-50 एल नामक रसायन सभी कृषि गोदामों पर उपलब्ध है जिसकी कीमत 336 रुपये प्रति लीटर है, जिस पर 50 प्रतिशत अनुदान की सुविधा भी दी जा रही है। कार्यक्रम में परियोजना निदेशक, अपर जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, नहर विभाग के अधिशासी अभियंता, भूमि संरक्षण अधिकारी, विद्युत विभाग, पशुपालन, मत्स्य पालन, सिंचाई तथा कृषि से जुड़े विभागों के अधिकारीगण तथा जिले भर के प्रगतिशील किसान उपस्थित रहे।

एडीएम न्यायिक की अध्यक्षता में संपन्न हुआ किसान दिवस

कुशीनगर।

बैठक दौरान सर्व प्रथम जिला कृषि अधिकारी द्वारा पिछले माह में प्राप्त शिकायतों के संबंध में संबंधित विभागों से निम्तारण आख्या अपर जिलाधिकारी न्यायिक के समक्ष रखी गई।

माह जून 2025 के किमान दिवस का आयोजन आज कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रेम कुमार राय की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक दौरान सर्व प्रथम जिला कृषि अधिकारी द्वारा पिछले माह में प्राप्त शिकायतों के संबंध में संबंधित विभागों से निम्तारण आख्या अपर जिलाधिकारी न्यायिक के समक्ष रखी गई। इसके उपरांत कृषक बंधुओं द्वारा अपनी समस्याओं सेअवगत कराया गया। कृषक महेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा उर्वरक की अनुपलब्धता के मम्बन्ध में सहायक निबंधक सहकारिता को अवगत कराया गया। इस पर सहायक निबंधक महकारिता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद के सभी समितियों पर उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कृषक छोटेलाल सिंह द्वारा जनपद के कृषकों को जिप्सम एवं कृषि रक्षा रसायनों की समय से उपलब्धता हेतु जिला कृषि अधिकारी से मांग किया गया, जिस पर जिला कृषि अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद के राजकीय कृषि बीज भण्डारों पर जिप्सम एवं कृषि रक्षा रसायनों की उपलब्धता है, कृषको की मांग के अनुसार अतिरिक्त जिप्सम की उपलब्धता हेतु आश्वस्त किया। रामाधार कुशवाहा द्वारा अपर जिलाधिकारी न्यायिक से जनपद में चयनित एग्रीगेटर के रूप में एफ0पी0ओ0 एवं इन्डियन आयल, धुरियापार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर पराली प्रबंधन के सम्बन्ध में आने वाली समस्याओं के समाधान की मांग की गयी। कृषक राधेश्याम कुशवाहा द्वारा पकडियार माइनर के सफाई के सम्बन्ध में शिकायत दर्ज कराई गयी जिसपर मम्बंधित अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि माइनर के सफाई का कार्य जल्द ही उचित माध्यम द्वारा करा लिया जायेगा। इस अवसर पर जिला कृषि अधिकारी द्वारा अनुदान पर कृषि यंत्रों को प्राप्त करने हेतु आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर करने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, सहायक निदेशक मत्स्य, सहायक निदेशक रेशम, जिला प्रबंधक पी0सी0एफ0, सहायक अभियन्ता सिचाई खंड प्रथम, सहायक अभियन्ता सिंचाई खंड दितीय, सहायक अभियन्ता सहायक अभियन्ता बाढ़ खंड, अग्रणी जिला प्रबंधक, सहायक अभियन्ता विधुत, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, एवं जनपद के ममम्त अधिकारी उपस्थित रहें।

बिहार भेजी जा रही 30 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

देवरिया। पुलिस अधीक्षक विक्रान्त वीर के नेतृत्व में जनपद देवरिया में अवैध शराब कारोबार पर नकेल कसने के लिए चलाए जा रहे 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत लार थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बुधवार को लार थाना पुलिस ने मेहरौना चौकी क्षेत्र के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। पंजाब निर्मित रॉयल स्टेज ब्रांड की 30 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई है, जिसकी कुल अनुमानित कीमत करीब 8 लाख रुपये आंकी जा रही है। मुखबिर की सूचना पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने मौके से दो अंतरराज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान बिहार के खगरिया जनपद के बेलदौर थाना क्षेत्र निवासी बिट्टू शाहू और बेगूसराय जनपद के बछवारा थाना क्षेत्र के अजय साहनी के रूप में हुई है। दोनों तस्कर अवैध शराब को पंजाब से बिहार ले जा रहे थे और उत्तर प्रदेश को पार करने के दौरान लार पुलिस की सक्रियता से धर दबोचे गए। पुलिस टीम ने न केवल शराब की 30 पेटियां बरामद कीं, बल्कि तस्करी में प्रयुक्त बोलेरो वाहन (पंजीकरण संख्या PB08EN0839) को भी जब्त कर लिया। बरामद माल और वाहन को कब्जे में लेकर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। इस कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक लार उमेश कुमार बाजपेयी, चौकी प्रभारी मेहरौना धर्मेन्द्र मिश्र, हेड कांस्टेबल राजकुमार सरोज, कांस्टेबल मिठाई लाल यादव और प्रकाशपति गौतम शामिल रहे।

भैसहा घाट का पीपा पुल डूबा : गंडक नदी का 70 हजार क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज,जलस्तर बढ़ा

नेबुआ नौरंगिया,कुशीनगर ।

नेपाल के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के कारणगंडक नदी का जलस्तर लगातार बदल रहा है।वाल्मीकिनगर गंडक बराज पर बुधवार सुबह 7 बजेपानी का डिस्चार्ज 30 हजार क्यूसेक था। दोपहर 12बजे तक बढ़कर 70 हजार क्यूसेक तक पहुंच गया। जिला प्रशासन और गंडक बराज के कर्मचारी अलर्ट परहैं। बराज कर्मी नेपाल के बरघाट सूचना केंद्र से लगातारसंपर्क में हैं।
खड़ा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों में लोगचिंतित हैं। प्रशासन के अनुसार 3 लाख क्यूसेक सेअधिक डिस्चार्ज होने पर ही गांवों में पानी घुस सकताहै। बढ़े जलस्तर के कारण भैसहा घाट का पीपा पुलपानी में डूब गया है। खड्डा एसडीएम मोहम्मद जफर ने बताया कि मानसून सेपहले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बाढ़ चौकियांऔर शरणालय सक्रिय कर दिए गए हैं। शासन के निर्देशपर तीन महीने का राशन आवंटित किया गया है।
बाढ़खंड और गंडक बराज के कर्मचारियों से निरंतर संपर्कबना हुआ है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अफवाहों से बचने की अपील की है।

दिव्यांग बच्चों के सपनों को मिलेगा नया आसमान, 20 जून से जनपद में शुरू होंगे विशेष पुनर्वास शिविर

देवरिया।

जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अपीलः दिव्यांग बच्चों के भविष्य संवारने में दें सहभागिता

दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्यधारा में लाने और उन्हें स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देशन में जिले के सभी विकासखंडों में 20 जून से विशेष पुनर्वास शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दिव्यांग बच्चों को चिन्हित कर उन्हें जरूरी उपकरण, स्वास्थ्य सेवाएं व अन्य सहायक संसाधन प्रदान किए जाएंगे।
यह कार्ययोजना इलाहाबाद उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति के निर्देशों के क्रम में संचालित की जा रही है, जिसमें जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और मेडिकल बोर्ड की संयुक्त भागीदारी होगी। शिविरों में चिन्हित बच्चों को कृत्रिम अंग, व्हीलचेयर, स्मार्ट केन, ब्रेल किट, एम.आर. किट, वॉकर, सी.पी. चेयर, ट्राईसाइकिल, बैसाखी आदि जरूरी सहायक उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही, उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए ब्लॉक स्तर पर मेडिकल बोर्ड की टीम मौजूद रहेगी और पात्र बच्चों को यूडीआईडी कार्ड भी जारी किए जाएंगे। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पाण्डेय इस पूरे कार्यक्रम के प्रशासनिक क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निभाएंगे। ब्लॉकवार शिविरों की तिथियां भी तय कर दी गई हैं, जिनकी शुरुआत 20 जून को गौरीबाजार से होगी और अंतिम शिविर 16 जुलाई को देसाई देवरिया में आयोजित किया जाएगा। शिविर स्थल पर किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर दिव्यांगजन मेडिकल बोर्ड के नोडल अधिकारी डॉ. अजय शाही से मोबाइल नंबर 9695211111 पर संपर्क किया जा सकता है। वहीं, प्रशासनिक समन्वय हेतु दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी प्रियंका चौधरी से भी संपर्क किया जा सकता है। इस संबंध में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने समस्त जनपदवासियों से भावुक अपील करते हुए कहा है कि समाज का कोई भी बच्चा अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण पीछे न छूटे, इसके लिए प्रशासन पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। आमजन से अपेक्षा है कि वे इस पुनीत कार्य में बढ़-चढ़कर सहभागिता करें और ऐसे बच्चों के भविष्य को रोशन करने में सहायक बनें।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का लाभ, परिवार को मिले दो लाख रुपए

नेबुआ नौरंगिया, कुशीनगर। भारत सरकार की महात्वांकांक्षी योजना (प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना) के तहत बडौदा यू.पी. बैंक की शाखा नौरंगिया चौराहा की ओर से मृतक खाताधारक की पत्नी (नामिनी) को रुपये दो लाख का चेक सौंपा गया।नेबुआ नौरगिया विकास खंड के विशुनपुरा खुर्द निवासी मृतक शोभित कुमार गुप्ता का बडौदा यू.पी. बैंक की शाखा नौरंगिया चौराहा में खाता था वह अपने खाते में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 436 रूपये वार्षिक में बीमा कराये थे, शोभित के निधन के बाद उनकी पत्नी प्रेमशिला गुप्ता को शाखा प्रबंधक श्री नवीन मद्धेशिया के द्वारा दो लाख रुपये का चेक सौंपा गया। इस दौरान कार्यालय सहायक प्रमोद कटियार, बीसी सुपरवाईजर गौतम गोंड, सीएसपी संचालक देवेंद्र कुमार गुप्त, गीता कुशवाहा एवं बैंक ग्राहक बंधु आदि मौजूद रहें। शाखा प्रबंधक ने ग्राहकों को सुझाव दिए कि आप लोग अपने खाते से जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा और अटल पेंशन जरूर कराये और सरकार के इन सारी लाभप्रद योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ उठाये ! वहां मौजूद ग्राहकों ने बडौदा यू.पी.बैंक नौरंगिया चौराहा के शाखा प्रबंधक व सीएसपी संचालकों का आभार जताया।

ग्राम प्रधान ने जर्जर तार,पोल बदलने की सहायक अभियंता से की मांग

तमकुही राज कुशीनगर ।

तमकुही विकास खण्ड के गांव लछिया देवरिया के ग्राम प्रधान ने विजली विभाग के अधिकारी को शिकायत पत्र देकर जर्जर एल्मुनियम तार,लौहे के तार को बदलने की मांग करते हुए कहा कि जर्जर तार से आये दिन घटना व दुर्घटना होती रहती है।ग्राम प्रधान ने इसे तत्काल बदलवाने की मांग की है। उक्त गांव के ग्राम प्रधान श्रीराम यादव ने विजली विभाग के अधिकारी को दीये शिकायत पत्र में लिखा है कि उसके ग्राम सभा मे लगे एल्मुनियम के तार से बिजली की आपूर्ति होती है।लेकिन उक्त तार पूरी तरह जर्जर हो गया है।जो आये दिन टूटकर गिरता रहता है।जिससे घटना व दुर्घटना होती रहती है।यहा के लोगों में भय बना रहता कि कही तार टूटकर गिर न जाये।ग्राम प्रधान ने बिजली विभाग के अधिकारियों से तार बदलकर नया लगाने की मांग किया है। जब कि विजली विभाग के एसडीओ ने बताया की उस क्षेत्र में जो कर्मचारी काम करता है उसका ट्रान्सफर हो जाने से जर्जर तार नही बदला गया है।दूसरे कर्मचारी के आने के बाद जर्जर तार को बदल दिया जाएगा।

भाजपा का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है- रजनीकांत

कुशीनगर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केन्द्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित विकसित भारत का अमृतकाल सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण के 11 वर्ष पर कसया मण्डल की संकल्प सभा खदहीं प्राथमिक विद्यालय में सम्पन्न हुई जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी ने सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य सत्ता प्राप्ति नहीं बल्कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। पूर्व विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारे देश ने बीते 11 वर्षों में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मार्ग पर ऐतिहासिक प्रगति की है। उनके मजबूत और निर्णायक नेतृत्व में भारत ने हर चुनौती का सामना करते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का साहस दिखाया है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और हम सभी का यह साझा संकल्प है कि हम एक नए, आत्मनिर्भर, सुरक्षित, सशक्त और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएँगे। यही प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है और यही 140 करोड़ देशवासियों का लक्ष्य बन चुका है। विशिष्ट अतिथि जिला मंत्री विवेकानंद शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के %सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के मंत्र ने देश के हर नागरिक को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा है। आज देश का हर वर्ग और हर क्षेत्र एक साझा संकल्प के साथ विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। पूर्व मण्डल अध्यक्ष अनिल प्रताप राव ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में देश ने वो भयावह दिन देखे हैं जब एक के बाद एक आतंकी हमले होते थे, और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती थी। कांग्रेस ने राष्ट्र की सुरक्षा को तुष्टीकरण की राजनीति के अधीन कर दिया। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है, भारत की नीति में एक ऐतिहासिक बदलाव आया है। अब भारत केवल सुनता नहीं है, सीधा, कठोर और निर्णायक जवाब देता है ।
जिला मीडिया प्रभारी विश्वरंजन कुमार आनन्द, पूर्व मण्डल अध्यक्ष रामायण कुशवाहा, कुशीनगर मण्डल अध्यक्ष आद्या पाण्डेय, मण्डल उपाध्यक्ष पवन दूबे ने भी सम्बोधित किया। अध्यक्षता मण्डल अध्यक्ष अमर नाथ कुशवाहा तथा संचालन मण्डल महामंत्री शम्भू गुप्ता ने किया। इस अवसर पर कन्हैया लाल कुशवाहा, रामायण प्रसाद,श्याम बिहारी कुशवाहा, सत्यनरायण निषाद, धीरेन्द्र सिंह,चन्द्रशेखर सिंह, मिथिलेश सिंह, जयप्रकाश दूबे, अजीत गुप्ता आदि उपस्थित थे।

हमारे लिए बुद्ध विषय पर आयोजित हुई संगोष्ठी

रामकोला (कुशीनगर)। रामकोला में स्थित शिवकुमारी देवी दलदपट शाही महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान, साखी पत्रिका और एसडीडीएस वीमेंस कालेज के संयुक्त तत्वावधान 18-06-2025 को ÷हमारे लिए बुद्ध÷ पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। जिसकी संचालिका अंशुप्रिया थी व कार्यक्रम की संयोजिका महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ मनीषा सिंह शाही ने सबका स्वागत और अभिनन्दन किया। उद्घाटन समारोह का प्रारम्भ साखी पत्रिका के संपादक और प्रेमचंद साहित्य संस्थान के निदेशक प्रो सदानंद शाही के प्रस्तावना अपने वक्तव्य में कहा कि मनो भव- अर्थात मनुष्य बनिये और अपने भीतर करूणा भरिए। इसके बाद बीएचयू के राजनीति विज्ञान विभाग की पूर्व अध्यक्ष प्रो शुभा राव अपने उद्घाटन वक्तव्य में कहा कि आज हम जहा खड़े है वह बुद्ध की धरती है और ये अत्यन्त गर्व की बात है। वक्तव्य युवा इतिहासकार शुभनीत कौशिक जी कहा ने कि कहने के साथ साथ करना भी चाहिए । विशिष्ट वक्तव्य के जाने माने कवि प्रकाश उदय ने बोला कि दुनिया के लिए दुःख,दुःख के लिए हम,हमारे लिए बुद्ध इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के रहे राम सुधार सिंह जी जातक कथाओं के माध्यम से बुद्ध की वाणी का संदेश दिया साथ ही कार्यक्रम में डॉ सूजित व जनता इंटर कॉलेज के भूतपूर्व प्रधानाचार्य श्री हरेंद्र सिंह महाविद्यायल के प्रवक्तागण व शिक्षक,शिक्षिकाएं व छत्राएं मौजूद रहे।

आग लगने से कट्रैन के दो घर जलकर खाक

मनसाछापर/ कुशीनगर । जटहा बाजार थाना क्षेत्र के कण्ठीछपरा में बीती रात करीब 11 बजे अज्ञात कारणों से लगी आग में दो कटरेन वाले घर जलकर राख हो गये। इसमें लाखों रुपयों की क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार कंठी छपरा गाँव के दोपही टोला निवासी सुदर्शन व सुरेन्द्र पुत्रगण राम प्रसाद का ईंट की दीवाल पर कटरेन व फूस के टाट लगे घर थे जिसमें बीती रात्रि करीब 11 बजे अज्ञात कारण से आग लग गयी और घर समेत घर का पूरा सामान आग की भेंट चढ़ गया। पास पड़ोस के जुटे लोगों के काफी मशक्कत के बाद आग बुझाने पर कामयाबी पायी । चूँकि दोनों घरों के रसोई घर में रखा रसोई गैस सिलिण्डर भी आग के कारण फट गया जिससे आग की लपटें काफी विकराल हो गईं थीं किन्तु गनीमत रही कि सामानों के अलावे किसी जान माल के नुकसान होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका है ।

सीईए बोले- वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत सकारात्मक, राजकोषीय घाटा व सरकारी कर्ज घटना बड़े सुधार

तिरुवनंतपुरम। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत के पास अवसर और संभावनाओं की कमी नहीं है। ऐसा मानना है देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंता नागेश्वरन का। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितताओं के बावजूद भारत चमकदार जगह के रूप में सामने आया है। देश की अर्थव्यवस्था में निरंतर मजबूती दिखी, जो आज के कठिन वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए उल्लेखनीय उपलब्धि है। फरवरी, 2022 से शुरू हुआ रूस-यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया में जारी हिंसक संघर्ष, इस्राइल और ईरान के चिंताजनक टकराव, ईंधन और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल की आशंकाओं के बीच एक साक्षात्कार में नागेश्वरन ने कहा, वर्ष 2022 से वैश्विक स्तर पर संघर्ष और व्यवधान लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब ये ज्यादा तीव्र और अप्रत्याशित हो गए हैं, जिससे दुनिया भर में आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़ी चिंता पैदा हुई है। हालात विकास के लिए और भी जटिल बन गए हैं। आज वैश्विक माहौल लगभग सभी देशों के लिए कठिन हो गया है। ऊपर की तरफ जाने की संभावनाओं से अधिक नीचे गिरने का जोखिम बढ़ गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंता नागेश्वरन ने

कहा, यह स्थिति केवल भारत की नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने यह चुनौती बड़ी होती जा रही है। हालांकि, इस कठिन परिदृश्य में भी भारत अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है। देश की अर्थव्यवस्था एक सकारात्मक उदाहरण पेश करती है। नागेश्वरन ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था ने 2020 में फैली कोविड-19 महामारी के बाद अच्छी रिकवरी की है। देश में मजबूत आर्थिक वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही भारत का राजकोषीय घाटा और सरकारी कर्ज भी कम हुआ है। आर्थिक मोर्चे पर ये बड़े सुधार हैं। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और इसका असर भारत और अमेरिका के 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड पर भी हुआ है। बॉन्ड की उपज में अंतर कम होने से ये अंतर साफ दिख रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए भारत की लगभग 6.5 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने 2008 में आई वैश्विक वित्तीय मंदी के बाद के दौर का उल्लेख करते हुए कहा कि बीते 17-18 साल में वैश्विक आर्थिक माहौल पूरी तरह अनुकूल नहीं रहा है। नागेश्वरन ने बताया कि भारत सरकार देश की अर्थव्यवस्था को 7 प्रतिशत या उससे अधिक की दर से बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हालांकि, आज की अनिश्चित और कठिन वैश्विक स्थितियों में भी 6.5 प्रतिशत की दर को बनाए रखना एक मजबूत उपलब्धि मानी जानी चाहिए। भारत विपरीत परिस्थितियों में भी स्थायित्व और विकास की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए हैं।

एक नजर

उपलब्धिः भारत में बने खिलौनों की वैश्विक बाजार में जबरदस्त मांग; छोटा भीम से लेकर मोटू-पतलू तक हो रहे निर्यात

मुंबई । भारत अब खिलौनों का आयात करने के बजाय निर्यात कर रहा है। छोटा भीम से लेकर मोटू-पतलू तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे। यहां बने खिलौनों की गुणवत्ता दुनियाभर के मानकों से बेहतर है। शून्य से 16 साल तक के बच्चों के खिलौने बनाने वाली कंपनियां अपने उत्पादों के विदेशी बाजारों में पहुंचाने से उत्साहित हैं। यह स्थिति सिर्फ दो साल में बदली है। यहां के खिलौने स्वास्थ की दृष्टि से भी बड़े पैमाने पर परखे हुए हैं। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), मुंबई के पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला (डब्ल्यूआरओएल) के वैज्ञानिक और निदेशक अद्भुत सिंह ने कहा, बीआईएस मानकों ने घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों में भारतीय खिलौनों की बिक्री बढ़ाने में सहायता की है। उन्होंने कहा, भारतीय मानक हमारी मौसम स्थितियों और अन्य घरेलू जरूरतों के अनुसार बनाए गए हैं। जीटीआरआई की रिपोर्ट के अनुसार, भारत का खिलौना निर्यात 2023-24 में मामूली रूप से घटकर 15.23 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी डॉलर रह गया, जो पिछले वर्ष 15.38 करोड़ अमेरिकी डॉलर था। नए आंकड़ों के अनुसार भारत में 1,640 बीआईएस-प्रमाणित खिलौना उद्योग हैं, जिनमें से 1,165 लाइसेंस गैर-इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों और 475 इलेक्ट्रिक खिलौनों के लिए हैं।

रिकॉर्ड कीमतों के बावजूद दुनियाभर के केंद्रीय बैंक बढ़ाते रहेंगे स्वर्ण भंडार, डॉलर से बना सकते हैं दूरी

नई दिल्ली । आर्थिक अनिश्चितताओं और कई देशों में तनाव के बीच दुनियाभर के केंद्रीय बैंक सोने की खरीदारी आगे भी जारी रखेंगे। इसके साथ ही, वे अमेरिकी डॉलर से दूरी बनाने की भी तैयारी कर रहे हैं। विश्व स्वर्ण परिषद (डब्ल्यूजीसी) की ओर से मंगलवार को जारी 2025 सेंट्रल बैंक्स गोल्ड रिजर्व सर्वे के मुताबिक, रिकॉर्ड कीमतों और लगातार 15 वर्षों से खरीद के बावजूद केंद्रीय बैंकों का सोने के प्रति आकर्षण अब भी बरकरार है। सर्वे के मुताबिक, आर्थिक अनिश्चितता और कई देशों में संघर्ष केंद्रीय बैंकों को भारी पड़ रहा है। इसलिए, वे जोखिम से बचने के लिए स्वर्ण भंडार और बढ़ाना चाहते हैं। सर्वे में शामिल 95 फीसदी केंद्रीय बैंकों का कहना है कि वे अगले 12 महीने में स्वर्ण भंडार में वृद्धि जारी रखेंगे। उभरते बाजारों एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के 48 फीसदी केंद्रीय बैंक 12 महीनों में स्वर्ण भंडार बढ़ाना चाहते हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के 21 फीसदी केंद्रीय बैंकों की भी खरीद जारी रखने की योजना है। सर्वे में एक और अहम ट्रेंड सामने आया है कि आने वाले वर्षों में वैश्विक रिजर्व में अमेरिकी डॉलर का हिस्सा घट सकता है। 73 फीसदी केंद्रीय बैंकों ने पांच वर्षों में डॉलर होल्डिंग में बड़ी गिरावट का अनुमान जताया है।?यूरो, रेनमिन्बी (चीनी मुद्रा) और सोने में निवेश बढ़ने की उम्मीद है। केंद्रीय बैंकों के सोने के प्रति आकर्षण के तीन मुख्य कारक हैं। पहला...85 फीसदी केंद्रीय बैंकों का कहना है, संकट में सोने का प्रदर्शन शानदार रहा है। दूसरा... 80 फीसदी मानते हैं कि लंबी अवधि में अच्छा मुनाफा देता है। तीसरा...81 फीसदी इसे पोर्टफोलियो को प्रभावी बनाने में मददगार मानते हैं। यूगॉव के साथ मिलकर किए गए सर्वे के मुताबिक, घरेलू स्तर पर सोने का भंडारण करने वाले केंद्रीय बैंकों की संख्या 2025 में बढ़कर 59 फीसदी पहुंच गई है। 2024 में 41 फीसदी केंद्रीय बैंक ही अपने ही देश में सोना रखते थे। डब्ल्यूजीसी के मुताबिक, केंद्रीय बैंकों ने लगातार तीसरे साल 1,000 टन से ज्यादा सोना खरीदा है। पिछले 10 वर्षों में औसतन हर साल 400 से 500 टन सोना खरीदा जाता था, लेकिन अब यह आंकड़ा काफी बढ़ गया है।

जापान के निर्यात में सालाना आधार पर मई में 1.7 प्रतिशत की गिरावट

तोक्यो । जापान के निर्यात में मई महीने में गिरावट आई है। अमेरिका को मोटर वाहनों के निर्यात में सालाना आधार पर करीब 25 प्रतिशत की भारी गिरावट इसकी मुख्य वजह रही। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि निर्यात में सालाना आधार पर 1.7 प्रतिशत की गिरावट आई जो विश्लेषकों द्वारा पूर्वानुमानित गिरावट से कम है। आयात में 7.7 प्रतिशत की गिरावट आई, जो कमजोर घरेलू मांग को दर्शाता है। यह अप्रैल में दर्ज दो प्रतिशत की गिरावट से भी बदतर है। वहीं व्यापार घाटा मई में 637.6 अरब येन या 4.4 अरब डॉलर रहा। जापान अभी तक शुल्क मुद्दे को सुलझाने के लिए अमेरिका के साथ किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाया है। प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने इस सप्ताह की शुरुआत में कनाडा में जी-7 शिखर सम्मेलन से इतर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद कहा था कि दोनों पक्ष कुछ बिंदुओं पर सहमत नहीं हो पाए हैं। अमेरिका ने जापान के मोटर वाहनों व उसके घटकों के निर्यात पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क और अन्य वस्तुओं पर 24 प्रतिशत शुल्क लगाया है।

एफटीए, व्यापार, निवेश को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा के लिए गोयल पहुंचे लंदन

नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के क्रियान्वयन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने तथा दोनों देशों के बीच व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने के तरीकों का पता लगाने के लिए दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर लंदन में हैं। बुधवार को आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। इस यात्रा के दौरान गोयल ब्रिटेन के व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, ''दोनों नेता एफटीए पर हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा इसे अंतिम रूप देने और कार्यान्वयन के लिए एक स्पष्ट, समयबद्ध खाका तैयार करेंगे। भारत और ब्रिटेन ने छह मई को एफटीए पर सहमति बनने की घोषणा की थी। इस समझौते का उद्देश्य श्रम-प्रधान भारतीय निर्यात जैसे चमड़ा, जूते और कपड़े पर शुल्क समाप्त करना जबकि व्हिस्की तथा कारों जैसे ब्रिटेन के उत्पादों के आयात को आसान बनाना है। इसका लक्ष्य 2030 तक दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार को दोगुना करके 120 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना भी है। समझौते पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर होना और इसका क्रियान्वयन होना बाकी है। गोयल, ब्रिटेन की राजकोष चांसलर रेचल रीव्स से भी मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक प्राथमिकताओं, वित्तीय सहयोग एवं निवेश सुविधा पर चर्चा करेंगे। रचनात्मक उद्योगों तथा नवाचार-संचालित क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं तलाशने के लिए उनकी संस्कृति, मीडिया एवं खेल मंत्री लिसा नैंडी से भी मिलने की योजना है। बयान में कहा गया है, ''ये बैठकें वैश्विक व्यापार जगत के नेताओं, निवेशकों एवं नीति विशेषज्ञों को एक साथ लाएंगी, ताकि भारत-ब्रिटेन आर्थिक गलियारे की रणनीतिक रूपरेखा तथा प्रस्तावित एफटीए के परिवर्तनकारी प्रभाव पर विचार-विमर्श किया जा सके। मंत्री, वाणिज्यिक संबंधों को गहरा करने और सीमा पार निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पोत परिवहन, वित्तीय प्रौद्योगिकी, लॉजिस्टिक्स तथा उन्नत विनिर्माण सहित प्रमुख क्षेत्रों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) और उद्योग हितधारकों के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 के 20.36 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 21.34 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया था।

भारत वैश्विक अनिश्चितता के बीच बेहतर स्थिति में है : मुख्य आर्थिक सलाहकार

तिरुवनंतपुरम । मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत एक बेहतर स्थिति में बना हुआ है। उन्होंने मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश के स्थिर आर्थिक प्रदर्शन की ओर इशारा करते हुए यह बात कही। सीईए ने कहा कि कहा कि 2022 से संघर्ष एवं व्यवधान वैश्विक परिदृश्य का हिस्सा रहे हैं लेकिन वे अब अधिक अप्रत्याशित हो गए हैं। इससे समग्र परिवेश चाहे राजनीतिक, आर्थिक या सुरक्षा से संबंधित हो दुनिया भर में वृद्धि के लिए कहीं अधिक चुनौतियां पेश कर रहे हैं। नागेश्वरन ने पश्चिम एशिया में यूक्रेन-रूस, भारत-पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्षों और शुल्क युद्धों के कारण बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे किए गए सवाल पर कहा कि आप कह सकते हैं कि सकारात्मक संभावनाओं पर कहीं न कहीं ये स्थितियां हावी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, यह कई देशों को प्रभावित कर रही हैं। सीईए ने कहा, ''कुछ हद तक यह कहा जा सकता है कि आज वैश्विक परिवेश चाहे वह राजनीतिक हो, आर्थिक हो या सुरक्षा से संबंधित हो, वृद्धि के लिए काफी जटिल और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है...

भारत ने 13 साल में वैश्विक निर्यात में सबसे तेज गति से बढ़ाई हिस्सेदारी; कैसे हासिल की 6.3 फीसदी की रफ्तार?

मुंबई । कोरोना महामारी, आर्थिक मंदी की आशंका और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत के निर्यात में 2010 से 2023 तक लगातार वृद्धि का रुख रहा। 13 वर्षों की इस अवधि में भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में वैश्विक निर्यात में अपनी हिस्सेदारी सबसे तेज रफ्तार से बढ़ाने में कामयाब रहा। इस दौरान भारत के निर्यात की वृद्धि दर 6.3 फीसदी रही, जो देश के व्यापार क्षेत्र की मजबूती को बताता है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (अंकटाड) की रिपोर्ट के हवाले से एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा, निर्यात के मोर्चे पर भारत का प्रदर्शन चीन, यूरोपीय संघ एवं अमेरिका जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में और भी अधिक उल्लेखनीय है। 2010 से 2023 के बीच चीन का निर्यात 6.1 फीसदी बढ़ा। यूरोपीय संघ और अमेरिका ने 3.9-3.9 फीसदी की वृद्धि दर्ज की। रूस और जापान के

निर्यात हिस्से में मामूली बढ़ोतरी या स्थिरता रही। अधिकारी ने कहा, घरेलू निर्यात में वृद्धि का रुझान भारत की व्यापार नीतियों, सेवा एवं विनिर्माण क्षेत्रों की प्रभावशीलता और निर्यात संवर्धन पहल के प्रभाव को दर्शाता है, जिसने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में देश के एकीकरण को बढ़ाने में योगदान दिया है। देश का कुल निर्यात 13 वर्षों की अवधि में करीब तीन गुना बढ़ा है। वित्त वर्ष 2009-10 में देश से 274.8 अरब डॉलर का निर्यात किया गया था, जो 2022-23 में 2.82 गुना बढ़कर 776.3 अरब डॉलर पहुंच गया। 2024-25 के दौरान भारत ने कुल 825 अरब डॉलर का निर्यात किया। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (फियो) के मुताबिक, भारत ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 1,000 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य रखा है। अमेरिकी टैरिफ की घोषणा के बाद देश से रत्न-आभूषण निर्यात मई, 2025 में सालाना आधार पर 15.81 फीसदी घटकर 226.34 करोड़ डॉलर रह गया। एक साल पहले की समान अवधि में 268.83 करोड़ डॉलर के रत्न-आभूषण निर्यात किए गए थे। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) के आंकड़ों के मुताबिक, तराशे गए हीरों का निर्यात 35.49 फीसदी घटकर 94.97 करोड़ डॉलर रहा। हालांकि, सोने के आभूषणों का निर्यात पिछले महीने सालाना आधार पर 17.24 फीसदी बढ़कर 99.75 करोड़ डॉलर पहुंच गया। मई, 2024 में यह आंकड़ा 85.08 अरब डॉलर रहा था। जीजेईपीसी चेयरमैन किरीट भंसाली ने कहा कि अमेरिका की ओर से टैरिफ की घोषणा के कारण मई में रत्न-आभूषण के निर्यात में गिरावट आई है। पश्चिम एशिया में तनाव के कारण सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग बढ़ने से स्वर्ण आभूषणों का निर्यात बढ़ा है।

एसोचैम का सर्वे : चुनौतियों के बीच मजबूती से बढ़ रही देश की अर्थव्यवस्था; डिजिटल परिवर्तन से तैयार हो रहे अवसर

नई दिल्ली । बदलते वैश्विक आर्थिक माहौल के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। बढ़ती लागत, नियामकीय बोझ और अन्य चुनौतियों के बावजूद बड़ी कंपनियां निर्यात के मोर्चे पर अपनी भागीदारी निभाते हुए प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हैं। इसके अलावा, विनिर्माण क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जबकि डिजिटल परिवर्तन से नए अवसर तैयार हो रहे हैं। एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) ने मंगलवार को जारी भारतीय आर्थिक विश्वास सर्वे में कहा, 250 करोड़ रुपये से अधिक की सालाना टर्नओवर वाली करीब 54 फीसदी कंपनियां देश के निर्यात में अपनी भागीदारी निभा रही हैं। वाहन एवं इससे जुड़े उपकरण, ऊर्जा, आईटी-आईटीईएस, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स जैसे क्षेत्रों में बड़ी कंपनियों का दबदबा है। हालांकि, 250 करोड़ रुपये या उससे कम की सालाना टर्नओवर वाली करीब 76 फीसदी छोटी कंपनियों ने निर्यात में किसी भी प्रकार की भागीदारी की जानकारी नहीं दी है। इससे स्पष्ट है कि निर्यात तंत्र को मजबूत करने के लिए अधिक नीतिगत प्रोत्साहन और संस्थागत समर्थन की जरूरत है। सर्वे में शामिल 47 फीसदी कंपनियों ने बुनियादी ढांचा, कुशल श्रम और फंडिंग की लागत में मामूली बढ़ोतरी का संकेत दिया है। क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर सर्वे में कहा गया है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने कई क्षेत्रों में निर्यात के साथ मजबूत तंत्र भी विकसित किया है। इसके विपरीत, पश्चिम बंगाल, गोवा और केरल जैसे अन्य राज्यों ने विशिष्ट स्थान बनाए रखा हैं। इस भौगोलिक विविधता के लिए निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र आधारित रणनीतियों की जरूरत है। एसोचैम के महासचिव मनीष सिंघल ने कहा, भारतीय उद्योग लगातार उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन, अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए उसे और अधिक समर्थन की आवश्यकता है।

फास्टैग को लेकर नितिन गडकरी का बड़ा एलान; 3000 का वार्षिक पास लाएगी सरकार, 15 अगस्त से होगा प्रभावी

नई दिल्ली । केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फास्टैग को लेकर बड़ा एलान किया है। उनके एलान से निजी वाहनों को खासतौर पर फायदा होगा। उन्होंने बुधवार को 3000 रुपये के वार्षिक फास्टैग आधारित पास का एलान किया। यह पास 15 अगस्त से प्रभावी होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, हम 3,000 रुपये की कीमत वाला फास्टैग-आधारित वार्षिक पास पेश कर रहे हैं, जो 15 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा। यह एक्टिव होने की तारीख से एक साल या 200 यात्राओं तक के लिए वैध रहेगा। सक्रिय होने की तारीख से एक साल या 200 यात्रा, में से जो भी पहले होगा, तब तक यह मान्य होगा। यह पास विशेष रूप से गैर-व्यावसायिक निजी वाहनों जैसे कार, जीप और वैन के लिए डिजाइन किया गया है। नितिन गडकरी ने एक्स पर लिखा, एक ऐतिहासिक पहल के तहत 15 अगस्त 2025 से 3,000 की कीमत वाला FASTag आधारित वार्षिक पास शुरू किया जा है। यह पास सक्रिय होने की तिथि से एक वर्ष तक या 200 यात्राओं तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा। यह पास केवल गैर-व्यावसायिक निजी वाहनों (कार, जीप, वैन आदि) के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। यह देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा को संभव बनाएगा। उन्होंने आगे लिखा, वार्षिक पास को सक्रिय करने, नवीनीकरण के लिए जल्द ही राजमार्ग यात्रा एप और NHAI या MoRTH की वेबसाइट्स पर एक अलग लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे प्रक्रिया सरल और सुगम होगी। उन्होंने लिखा, यह नीति 60 किलोमीटर की सीमा के भीतर स्थित टोल प्लाजा के बारे में लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को संबोधित करती है और एक ही सुलभ लेनदेन के माध्यम से टोल भुगतान को सहज बनाएगी। केंद्रीय मंत्री ने यह भी लिखा, प्रतीक्षा समय घटाकर, भीड़ कम कर और टोल प्लाजाओं पर विवाद को समाप्त कर, वार्षिक पास नीति लाखों निजी वाहन चालकों के लिए तेज, सुगम और बेहतर यात्रा अनुभव के लिए प्रतिबद्ध है।

गिरावट के बाद घरेलू शेयर बाजार में लौटी हरियाली, सेंसेक्स-निफ्टी की सपाट शुरुआत

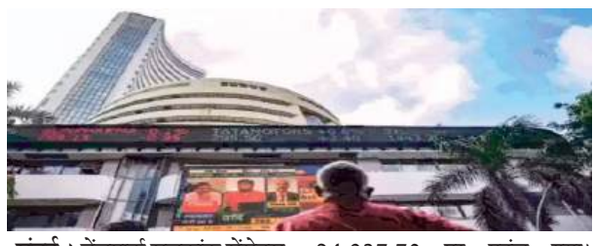

मुंबई । बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी बुधवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट के बाद वापस उछले।

विदेशी फंड के आने, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई बैंक जैसे ब्लू-चिप शेयरों में खरीदारी के कारण बाजार में तेजी आई। कारोबार की कमजोर शुरुआत के बावजूद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स बाद में उछला और 93.05 अंक बढ़कर 81,676.35 पर पहुंच गया। 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 42.80 अंक बढ़कर 24,896.20 पर पहुंच गया। बाद में बीएसई बेंचमार्क 228.13 अंक बढ़कर 81,812.04 पर और निफ्टी 82.25 अंक चढ़कर 24,937.70 पर पहुंच गया। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से इंडसइंड बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, टाइटन, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई बैंक सबसे ज्यादा फायदे में रहे।

कोटक महिंद्रा बैंक, पावर ग्रिड, एनटीपीसी और अदानी पोर्ट्स पिछड़ते नजर आए। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को 1,482.77 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने भी पिछले कारोबार में 8,207.19 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी और जापान का निक्केई 225 सूचकांक सकारात्मक क्षेत्र में कारोबार कर रहे थे, जबकि शंघाई का एसएसई कंपोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग लाल निशान पर दिखा। मंगलवार को अमेरिकी बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.44 प्रतिशत बढ़कर 76.79 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया सीमित दायरे में कारोबार करता दिखा। मौजूदा जोखिम-रहित भावनाओं और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने स्थानीय इकाई पर दबाव डाला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय में घरेलू इकाई में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया। यह डॉलर के मुकाबले 86.42 पर खुला, फिर शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले 86.25 के शुरुआती उच्च स्तर को छू गया। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 30 पैसे गिरकर 86.34 पर बंद हुआ था।

आर्थिक वृद्धि के चलते 2030 तक वैश्विक तेल मांग का अगुवाई करेगा भारत; इस दशक के अंत तक बढ़ी रहेगी मांग

नई दिल्ली ।

वैश्विक तेल मांग इस दशक के अंत तक तेजी से बढ़ती रहेगी। अमेरिका में सस्ता पेट्रोल और धीमी गति से इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने से खपत को समर्थन मिलने से शीर्ष आयातक चीन में यह 2027 में चरम पर होगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने अपने पूर्वानुमान में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

आईईए ने कहा, मांग 2029 तक चरम पर होगी, लेकिन अनुमान है कि इलेक्ट्रिक वाहनों में वृद्धि के कारण चीन में मांग पहले ही चरम पर पहुंच जाएगी। वैश्विक मांग कुछ वर्षों में चरम पर होगी। हालांकि, उत्पादक समूह पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) का मानना है कि खपत बढ़ती रहेगी, लेकिन खपत चरम पर पहुंचने का कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया है। आईईए की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, तेल की मांग 2029 तक 10.5 करोड़ बैरल प्रति दिन (बीपीडी) के उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी। फिर 2030 में थोड़ी गिरावट आएगी। वैश्विक उत्पादन क्षमता 2030 तक 50 लाख बीपीडी से अधिक बढ़कर 11.47 करोड़ बीपीडी होने का अनुमान है। इस्राइल और ईरान के बीच संघर्ष ने मध्य पूर्व की आपूर्ति के लिए जोखिम को उजागर किया है। इससे शुक्रवार को तेल की कीमतें 5 फीसदी बढ़कर 74 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कोई बड़ी बाधा नहीं आती है तो 2030 तक पर्याप्त आपूर्ति होगी। आईईए के कार्यकारी निदेशक फतिह बिरोल ने कहा, बुनियादी बातों के आधार पर आने वाले वर्षों में तेल बाजारों में अच्छी आपूर्ति होने की संभावना है। लेकिन हाल की घटनाओं ने तेल आपूर्ति सुरक्षा के लिए देशों के बीच तनाव एक प्रमुख मुद्दा है। इस वर्ष विश्व बाजार में आपूर्ति अच्छी दिख रही है, क्योंकि कोई बड़ा व्यवधान नहीं आया है और आपूर्ति में वृद्धि मांग से अधिक है। आईईए ने कहा, इस साल वैश्विक मांग में 720,000 बीपीडी की वृद्धि होगी, जो पिछले महीने के पूर्वानुमान से 20,000 बीपीडी कम है। आपूर्ति में 18 लाख बीपीडी की वृद्धि होगी, जो पिछले महीने से 200,000 बीपीडी अधिक है। इसका आंशिक कारण ओपेक और अन्य देशों द्वारा उत्पादन में वृद्धि है।

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को दी बधाई, जेम पोर्टल से सरकारी खरीद पर जताई खुशी

नई दिल्ली ।

उत्तर प्रदेश में जेम पोर्टल से सरकारी खरीद किए जाने की पहल पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने खुशी जताई है। उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर बधाई दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल के जरिये सरकारी खरीद बढ़ाने में उत्तर प्रदेश का खासा योगदान रहा है। उन्होंने पिछले पांच साल में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पोर्टल के जरिये की गई खरीद का डाटा भी साझा किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पत्र में लिखा कि गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस एक राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। इसके जरिये केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त संस्थानों और स्थानीय निकायों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की शुरू से अंत तक ऑनलाइन खरीद की जा सकती है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेम ने 5.43 लाख करोड़ रुपये के 72 लाख से अधिक के क्रय आदेश पूरे किए हैं। शुरुआत से लेकर अब तक जेम के जरिये 2.9 करोड़ से अधिक क्रय आदेशों के माध्यम से 14 लाख करोड़ से अधिक की खरीद की जा चुकी है। जेम अब 11 हजार से अधिक उत्पाद और 330 से ज्यादा सेवा श्रेणियों के साथ एक उपलब्धि खरीद मंच के रूप में काम कर रहा है। इस वृद्धि में उत्तर प्रदेश सरकार का योगदान काफी अहम है। केंद्रीय मंत्री ने पत्र में लिखा कि पिछले पांच वित्तीय वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जेम के जरिये की गई खरीद राज्य के विश्वास का प्रमाण है। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 26 नवंबर 2024 को आदेश जारी करके राज्य के खरीद नियमों में बदलाव किया और जेम को मान्यता दी। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता हूं। प्रदेश सरकार की यह पहल विभिन्न खरीद-संबंधी अधिसूचनाओं को एकीकृत करती है। इससे प्रक्रियाएं सरल हुई हैं और GeM को 100फीसदी अपनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

साथ ही जेम की पारदर्शिता, दक्षता, समावेशिता और खरीद को आसान बनाने की प्रक्रिया तेज हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेम को सरकारी क्रेताओं की सभी प्रकार की आवश्यकताओं के लिए वन-स्टॉप मार्केटप्लेस के रूप में स्थापित किया गया था। जेम पोर्टल के लिए उत्तर प्रदेश का प्रोत्साहन इस का प्रमाण है कि जब तकनीकी दृष्टिकोण, समावेशन और निष्पादन जुड़ता है तो पता चलता है कि डिजिटल इंडिया की संकल्पना से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की यह पहल अन्य राज्यों को भी GeM को तेजी से अपनाने की प्रेरणा देगी। ऐसा मुझे विश्वास है। केंद्रीय मंत्री ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि यूपी सरकार ने बीते पांच वित्तीय वर्ष में जेम पोर्टल से खरीद में बढ़ोतरी की है। इसमें साल 2020-21 में 4622 करोड़, 2021-22 में 11286 करोड़, 2022-23 में 12422 करोड़, 2023-24 में 20248 करोड़ और 2024-25 में 16 हजार करोड़ की खरीद की गई। खरीद करने में शहरी विकास विभाग सबसे आगे हैं।

MEGA
JOB FAIR
DELHI
An initiative by Indian Youth Congress
FREE REGISTRATION
19th June 2025
Talkatora Stadium, New Delhi
10:00 AM Onwards
100+ Companies
airtel
amazon
TATA
blinkit
HDFC BANK
Flipkart
Mahindra
zepto
AXIS BANK
More than 5000
Job opportunities
To Register Scan the
QR code or Call us:
8860832106, 9643345609,
9910821286, 8745961093
श्री सुरेन्द्र कुमार
पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष
किराड़ी जिला कांग्रेस कमेटी
संयोजक:-
रिपब्लिकन
मज़दूर संगठन
विजय कुमार भारती
पत्रकार, महासचिव: किराड़ी जिला